Kamal.Sandesh
kamalsandesh.org
KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-15 01-15 अगस्त, 2025 (पाक्षिक) ₹20

'भारत का टाइगर हिल है, भारत का टाइगर हिल रहेगा'

'वर्तमान मानसून सत्र राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का क्षण और विजय का उत्सव है'

नई दिल्ली में 26 जुलाई, 2025 को आयोजित 'कारगिल विजय दिवस समारोह' के दौरान शहीदों को नमन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 13 जुलाई, 2025 को सऊदी अरब के महामहिम प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान अल सऊद के साथ चर्चा करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 27 जुलाई, 2025 को 'मन की बात' कार्यक्रम सुनते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बैजयंत पांडा, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े एवं अन्य नेतागण

रुद्रपुर (उत्तराखंड) में 19 जुलाई, 2025 को 'उत्तराखंड निवेश महोत्सव 2025' को संबोधित करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

जयपुर (राजस्थान) में 17 जुलाई, 2025 को आयोजित 'सहकारिता एवं रोजगार महोत्सव' में भाग लेते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में 26 जुलाई, 2025 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर भारत के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **मानसून सत्र राष्ट्र के लिए गौरव का पल है, यह हमारी सामूहिक उपलब्धियों का सच्चा उत्सव है: नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान मानसून सत्र राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव...

08 **भारत में यह दौर हमारे पूरबी राज्यों का है: नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक...

10 **'भाजपा समृद्ध और विकसित पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है'**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जुलाई, 2025 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया...

17 **'भारत का टाइगर हिल है, भारत का टाइगर हिल रहेगा'**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली स्थित पार्टी केन्द्रीय...

21 **भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23-24 जुलाई को ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री माननीय सर कीर स्टारर ने...

लेख

विरासत का हस्तांतरण: मोदी जी ने वाजपेयी जी के 'विकसित भारत' के स्वप्न को कैसे साकार किया / **डॉ. के. लक्ष्मण** 18
विकसित भारत की ओर एक और बड़ा कदम, ब्रिटेन के साथ ट्रेड से अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा / **पीयूष गोयल** 26
समुद्री विकास को बढ़ावा देते हुए विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हुआ / **सर्बानंद सोनोवाल** 28
देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक कारगिल की वीरगाथा / **तरुण चुग** 30
मातृभूमि की सच्ची सेवा के लिए समर्पित मोदी सरकार के अविस्मरणीय 11 वर्ष / **राजकुमार चाहर** 32

अन्य

जनता के हाथों में शक्ति: भारत में सहकारी समितियों की त्वरित उन्नति और उनमें हो रहे बदलाव 12
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को दी मंज़ूरी 14
बीमा सखी योजना में 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं का नामांकन 15
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और एनएचएम के तहत 10.18 करोड़ महिलाओं की सर्विकल कैंसर की जांच की गई 16
कमल पुष्प 16
प्रधानमंत्री की मालदीव गणराज्य की यात्रा 22
राज्य में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ-साथ 81 हजार से ज्यादा रोजगार का सृजन हुआ: अमित शाह 24
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल का संकल्प 34

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

हम अपने किसान भाई-बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसी दिशा में आज प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र में पीछे रह गए जिलों में फसलों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही अन्नदाताओं की आमदनी भी बढ़ेगी।

(16 जुलाई, 2025)

जगत प्रकाश नड्डा

लंबे समय तक हमारे यहां हेल्थ का मतलब पहले बीमार पड़ो और फिर इलाज करवाओ होता था। वर्ष - 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हेल्थ पॉलिसी आई है। इसके तहत क्षेत्र के आधार पर नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गयीं।

(17 जुलाई, 2025)

अमित शाह

आज उत्तराखंड के रुद्रपुर से राज्य सरकार की 1,271 करोड़ रु. की विभिन्न परियोजनाओं का ई-लोकार्पण व ई-शिलान्यास किया। सुरक्षा, सड़क, पेयजल व महिला छात्रावास संबंधी इन कार्यों से प्रदेश में सुशासन व जनकल्याण को बढ़ावा मिलेगा। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटन, पवित्र धामों के कारण तीर्थ, मेहनतकश युवा शक्ति के कारण निवेश, उद्योग व अपार संभावनाओं का प्रदेश उत्तराखंड भाजपा सरकार में लोकसेवा, सुशासन, रोजगार व इनोवेशन से स्टार्ट-अप तक, विकास का सुंदर कालखंड देख रहा है। (19 जुलाई, 2025)

राजनाथ सिंह

उत्तर प्रदेश आज कानून, निवेश और उद्योग के नए मानक गढ़ रहा है। ब्रह्मोस जैसी परियोजनाएं न सिर्फ रक्षा क्षेत्र को मज़बूती दे रही हैं, बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार भी ला रही हैं।

(13 जुलाई, 2025)

बी.एल. संतोष

कूटनीति में असंभव को संभव बनाने के लिए अपार धैर्य, राष्ट्रीय हितों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता एवं विश्वबंधुत्व (वसुधैव कुटुम्बकम्) की भावना की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मालदीव के साथ ठीक यही किया।

(25 जुलाई, 2025)

धर्मेंद्र प्रधान

शिक्षा के क्षेत्र में भारत एवं ब्रिटेन एक नया अध्याय लिख रहे हैं। ब्रिटेन के छह विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोल रहे हैं। पिछले सप्ताह ही साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन भारत के गुरुग्राम शहर में हुआ।

(24 जुलाई, 2025)

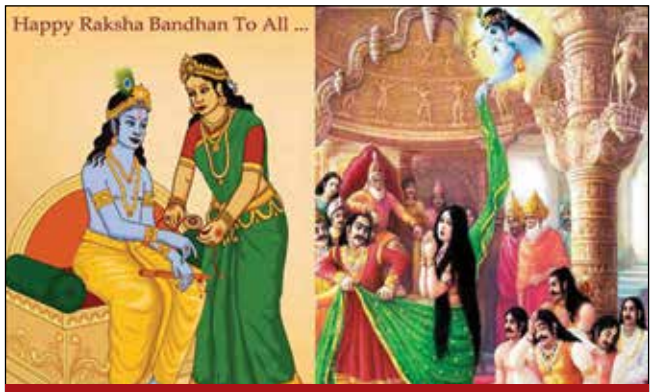

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
रक्षा बंधन (09 अगस्त)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

लोकतंत्र फलता-फूलता रहेगा

संपादकीय

वर्तमान मानसून सत्र के आरंभ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस सत्र को गौरव का क्षण एवं विजय उत्सव के रूप में परिभाषित किया, लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को बाधित करने पर तुला हुआ है। मानसून सत्र 2025 भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य एवं साहस को नमन करने तथा 'ऑपरेशन सिंदूर' की शानदार सफलता का उत्सव मनाने का अवसर है, फिर भी यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 21 जुलाई, 2025 से शुरू होने वाले सत्र का पहला सप्ताह कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के बार-बार व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिसके परिणामस्वरूप लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को प्रतिदिन कई बार स्थगित करना पड़ा। प्रायः कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर सदन को स्थगित करना पड़ा। इस स्थिति के चलते न तो कोई सार्थक चर्चा हो सकी और न ही कोई विधायी कार्य आगे बढ़ पाया। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र की गरिमा और संसदीय कार्य-संस्कृति के लिए अत्यंत चिंताजनक है और इससे संसद का सामान्य कामकाज सुचारू रूप से संचालित करना कठिन होता जा रहा है।

पहले ही दिन से यह स्पष्ट हो गया था कि विपक्ष चर्चा के बजाय टकराव का रास्ता चुनने का मन बना चुका है। लोकतंत्र में उपलब्ध सशक्त साधनों का उपयोग करने, प्रश्न पूछने, बहस करने, प्रस्ताव पेश करने या आलोचना करने के बजाय विपक्षी सदस्यों ने बार-बार सामान्य कार्यवाही को ठप करने का रास्ता चुना। इस रणनीति में दिखावे की राजनीति की गई, जिसमें सदन के अंदर बार-बार शोरगुल, नारेबाजी और तख्तियां दिखाई गईं। इस व्यवधान ने न केवल मंत्रियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाब देने से रोका, बल्कि नागरिकों को भी पारदर्शिता और जवाबदेही से भी वंचित किया। इस प्रकार, संसद का उद्देश्य, कानूनों और नीतियों पर खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना अधूरा रह गया और संसद में कोई भी कामकाज न होने के कारण करदाताओं का पैसा हर मिनट बर्बाद होता रहा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ और करिश्माई नेतृत्व में 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने की दिशा में राष्ट्र आगे बढ़ रहा है

विपक्ष द्वारा अपनाई गई रणनीति की व्यापक रूप से आलोचना की गई। अध्यक्ष श्री ओम बिरला और वरिष्ठ मंत्रियों ने व्यवधानों को 'अलोकतांत्रिक' करार दिया और विपक्ष से व्यवस्थित चर्चा की ओर लौटने का आह्वान किया। व्यवधानों के बारे में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि ऐसे व्यवहार से विपक्ष की धारणा और विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संसदीय लोकतंत्र में सरकार को चुनौती देने और विविध विचारों को सामने लाने के लिए एक मजबूत और मुखर विपक्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन यह भूमिका साक्ष्य-आधारित तर्कों और बहस के माध्यम से सबसे अच्छी तरह निभाई जा सकती है। इसके बजाय, केवल व्यवधान को प्राथमिकता देना, संसदीय प्रणाली के भीतर विरोधी आवाजों को सशक्त बनाने के लिए बनाए गए तंत्रों की अस्वीकृति के रूप में सामने आती है।

2025 के मानसून सत्र के व्यवधानों ने संसदीय लोकतंत्र की सेहत पर भी व्यापक रूप से सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय लोकतंत्र ने हमेशा बहस को महत्व दिया है, यहां तक कि व्यापक असहमतियों को भी तर्कपूर्ण संवाद के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। पारंपरिक बहस के स्थान पर बार-बार शोर और व्यवधान का सहारा लेना इस भावना को कमज़ोर करता है। यह जरूरी विधायी कार्यों से ध्यान भटकाता है और जनता को यह संकेत देता है कि संसद, राष्ट्रीय प्रगति को महत्व देने वाले स्थान की बजाय शोरगुल का अड्डा बन गई है। अगर गंभीरता से सोचें तो इस दृष्टिकोण से किसी भी संस्थान की विश्वसनीयता कम होने का खतरा बना रहता है। इससे विपक्ष को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि लगातार रुकावटों के कारण सरकारी कार्यों पर सवाल उठाने और उन्हें बेहतर बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका कमजोर हो जाती है।

संक्षेप में, 2025 का मानसून सत्र संसदीय हथकंडों के दुरुपयोग की एक चेतावनी है। तर्क-वितर्क और गठबंधन बनाकर अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के बजाय, विपक्ष ने अपनी विश्वसनीयता और संसद की प्रभावशीलता, दोनों को ही कमज़ोर कर दिया। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र में असहमति जताने की शक्ति के साथ-साथ उसे रचनात्मक रूप से व्यक्त करने की ज़िम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अपने स्वार्थ के लिए व्यवधान न केवल सरकार, बल्कि राष्ट्र की प्रगति को भी पीछे धकेलता है और उस व्यवस्था को कमज़ोर करता है जिसकी रक्षा के लिए विपक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

जब संसद को 'ऑपरेशन सिंदूर' की उल्लेखनीय सफलता का जश्न मनाने और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार तिरंगा फहराने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर राष्ट्र के साथ मिलकर खुशी मनानी चाहिए थी, तब कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा ऐसी रणनीति अपनाना अत्यंत निंदनीय है जिससे राष्ट्र ऐसे गौरवशाली क्षणों से वंचित रह गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ और करिश्माई नेतृत्व में 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने की दिशा में राष्ट्र आगे बढ़ रहा है और विपक्ष की मनोबल गिराने वाली चालों के बावजूद राष्ट्र संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र की रक्षा करेगा। जब तक राष्ट्र अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ प्रगति करता रहेगा, लोकतंत्र फलता-फूलता रहेगा। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

मानसून सत्र 2025 की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य

मानसून सत्र राष्ट्र के लिए गौरव का पल है, यह हमारी सामूहिक उपलब्धियों का सच्चा उत्सव है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2025 के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले 21 जुलाई को संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। मानसून सत्र में सभी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून नवाचार और नवीनीकरण का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में वर्तमान मौसम की स्थिति अनुकूल हो रही है जो कृषि के लिए लाभकारी पूर्वानुमान के समान है। श्री मोदी ने कहा कि वर्षा न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के समग्र आर्थिक ढांचे में बल्कि प्रत्येक परिवार की वित्तीय भलाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जानकारी के आधार पर इस वर्ष जलाशयों का स्तर पिछले दस वर्षों की तुलना में तीन गुना बढ़ गया है। श्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि यह वृद्धि आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान मानसून सत्र राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। यह भारत की विजय का उत्सव है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि इस उपलब्धि ने पूरे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रति नया उत्साह और उमंग जगाया है। श्री मोदी ने आगे कहा कि पूरी संसद– लोकसभा और राज्यसभा– के साथ-साथ जनता भी इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करने के लिए एकजुट है। उन्होंने कहा कि यह सामूहिक उत्सव भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण अभियानों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का काम करेगा।

केवल 22 मिनट में दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकाने ध्वस्त

श्री मोदी ने वर्तमान मानसून सत्र को भारत की विजय का उत्सव बताते हुए कहा कि दुनिया ने देश के सशस्त्र बलों की शक्ति और क्षमता देखी है। 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय सेना ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत सफलता के साथ हासिल किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत केवल 22 मिनट में भारतीय सेनाओं ने दुश्मनों के महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त कर दिया।

श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने बिहार में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस ऑपरेशन की घोषणा की थी और सशस्त्र बलों ने तेज़ी से

अपना पराक्रम साबित किया। श्री मोदी ने भारत की उभरती 'मेड इन इंडिया' रक्षा क्षमताओं में बढ़ती वैश्विक रुचि का उल्लेख करते हुए कहा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई उनकी बातचीत के दौरान विश्व नेताओं ने भारत के स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य उपकरणों की प्रशंसा की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जब संसद इस सत्र के दौरान एक स्वर में इस विजय का जश्न मनाएगी, तो यह भारत की सैन्य शक्ति को और ऊर्जावान और प्रोत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सामूहिक भावना नागरिकों को भी प्रेरित करेगी और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और विनिर्माण को गति प्रदान करेगी, जिससे भारत के युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।

अब तेज़ी से सिकुड़ रहा है नक्सलवाद और माओवाद का भौगोलिक विस्तार

श्री मोदी ने बताया कि नक्सलवाद और माओवाद का भौगोलिक विस्तार अब तेज़ी से सिकुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के सुरक्षा बल नए आत्मविश्वास और त्वरित प्रयासों के साथ नक्सलवाद और माओवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने गर्व के साथ कहा कि देश के सैकड़ों जिले अब नक्सल हिंसा की गिरफ़्त से मुक्त होकर आज़ादी की सांस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि भारत का संविधान हथियारों और हिंसा पर हावी है। उन्होंने कहा कि पूर्व 'रेड कॉरिडोर (हिंसा के लाल गलियारे)' क्षेत्र अब स्पष्ट रूप से 'ग्रीन ग्रोथ ज़ोन (हरित विकास क्षेत्र)' में बदल रहे हैं, जो देश के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है।

श्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि 2014 में जब उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला था, तब भारत पांच नाज़ुक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि उस समय वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में भारत दसवें स्थान पर था, लेकिन आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है और उस मुकाम के द्वार पर दस्तक दे रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से उबर चुके हैं, यह एक ऐसा बदलाव है जिसे वैश्विक संस्थाओं ने व्यापक रूप से मान्यता और सराहना दी है।

आज मुद्रास्फीति की दर लगभग 2 प्रतिशत के आसपास

श्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले भारत दो अंकों की मुद्रास्फीति से जूझ रहा था। उन्होंने कहा, "आज मुद्रास्फीति की दर लगभग 2 प्रतिशत के आसपास रहने से नागरिक राहत और बेहतर जीवन स्तर का अनुभव कर रहे हैं। कम मुद्रास्फीति और उच्च विकास दर एक मज़बूत और स्थिर विकास यात्रा को दर्शाते हैं।"

दुनिया को झकझोर देने वाला और आतंकवाद तथा उसके प्रायोजकों की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने वाले पहलगाम नृशंस हत्याकांड को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके जवाब में अधिकांश राजनीतिक दलों और राज्यों के प्रतिनिधियों ने दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र की सेवा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम बढ़ाया। उन्होंने इस एकीकृत कूटनीतिक अभियान की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में बेनकाब किया।

एकता की शक्ति और राष्ट्र को प्रेरित व ऊर्जावान बनाने वाली एकजुटता की भावना पर ज़ोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान मानसून सत्र 'विजय उत्सव' के रूप में इसी भावना को प्रतिबिंबित करेगा, भारत की सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय क्षमता का सम्मान करेगा और 140 करोड़ नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयास रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने राष्ट्र से सशस्त्र बलों की ताकत को पहचानने और उसकी सराहना करने का आग्रह किया। जनता और राजनीतिक दलों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एकता से मिलने वाली शक्ति और पूरे देश के एक स्वर में बोलने के प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी सांसदों से संसद में इस भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

राजनीतिक दलों और उनके संबंधित एजेंडों की विविधता को स्वीकार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दलीय हितों पर राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हित के मामलों में इरादों में सामंजस्य होना चाहिए। उन्होंने यह दोहराते हुए अपने संबोधन का समापन किया कि इस सत्र में राष्ट्र के विकास को गति देने, नागरिकों को सशक्त बनाने और भारत की प्रगति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई प्रस्तावित विधेयक शामिल होंगे। श्री मोदी ने सभी संसद सदस्यों को सार्थक एवं बेहतर गुणवत्ता वाली बहस के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्य बातें

- दुनिया ने देश की सैन्य क्षमता की ताकत देखी है; ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों ने 100 प्रतिशत सफलता के साथ अपना उद्देश्य हासिल किया, आतंक के साजिशकर्ताओं को उनके ठिकानों में ध्वस्त कर दिया
- देश ने कई हिंसक चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वह आतंकवाद हो या नक्सलवाद, लेकिन आज नक्सलवाद और माओवाद का प्रभाव तेजी से कम हो रहा है; संविधान बम और बंदूकों पर भारी पड़ा है। अतीत के लाल गलियारे अब विकास के हरित क्षेत्र बन रहे हैं
- डिजिटल इंडिया विश्व स्तर पर धूम मचा रहा है, यूपीआई कई देशों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है, यह फिनटेक की दुनिया में एक स्थापित नाम है
- पहलगाम नरसंहार ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और आतंकवाद तथा उसके केंद्र की ओर दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश भर के प्रतिनिधि इसमें पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने में एकजुट हैं ■

बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

भारत में यह दौर हमारे पूरबी राज्यों का है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। सावन के पवित्र महीने में बाबा सोमेश्वरनाथ के चरणों में शीश झुकाते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार के सभी निवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि की कामना की और आशीर्वाद लिया। श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह चम्पारण की भूमि है, एक ऐसी धरती जिसने इतिहास रचा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसी भूमि ने महात्मा गांधी को नई दिशा दी थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसी भूमि से मिली प्रेरणा अब बिहार के नए भविष्य को आकार देगी।

श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी तेज़ी से वैश्विक प्रगति का साक्षी बन रही है। उन्होंने कहा कि जो प्रभुत्व कभी केवल पश्चिमी देशों का था, वह अब पूर्वी देशों द्वारा साझा किया जा रहा है, जिनकी भागीदारी और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। श्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि पूर्वी देश अब विकास की नई गति प्राप्त कर रहे हैं। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह पूर्वी देश वैश्विक स्तर पर प्रगति कर रहे हैं, उसी तरह भारत में भी पूर्वी राज्यों का युग है। उन्होंने सरकार के इस संकल्प की पुष्टि की कि आने वाले समय में पूर्व में मोतिहारी का स्थान पश्चिम में मुंबई की तरह ही प्रमुख स्थान बन जाएगा।

> 21वीं सदी तेज़ी से वैश्विक प्रगति का साक्षी बन रही है। जो प्रभुत्व कभी केवल पश्चिमी देशों का था, वह अब पूर्वी देशों द्वारा साझा किया जा रहा है, जिनकी भागीदारी और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पूर्वी देश अब विकास की नई गति प्राप्त कर रहे हैं। जिस तरह पूर्वी देश वैश्विक स्तर पर प्रगति कर रहे हैं, उसी तरह भारत में भी पूर्वी राज्यों का युग है

पिछले 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए लगभग 9 लाख करोड़ रुपये आवंटित

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए बिहार को एक विकसित राज्य में रूपांतरित होना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में आज तीव्र प्रगति संभव है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकारें हैं। उन्होंने इस तथ्य के समर्थन में अंतर को दर्शाने के लिए आंकड़ों का हवाला दिया— पिछली सरकारों के 10 वर्षों के दौरान जब वे केंद्र में सत्ता में थे, बिहार को केवल लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मिले। श्री मोदी ने कहा कि यह श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध का एक रूप था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने बिहार के विरुद्ध प्रतिशोध की इस राजनीति को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनके शासन में बिहार के विकास के लिए लगभग 9 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह पिछली सरकार के तहत प्रदान की गई राशि से चार गुना अधिक है।

श्री मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि पिछले 11 वर्षों में देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं, जिनमें से लगभग 60 लाख अकेले बिहार में बने हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा नॉर्वे, न्यूज़ीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की कुल

जनसंख्या से भी अधिक है। श्री मोदी ने कहा कि अकेले मोतिहारी ज़िले में ही लगभग 3 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं और यह संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इस क्षेत्र के 12,000 से अधिक परिवारों को आज उनके नए घरों की चाबियां मिल गई हैं। इसके अतिरिक्त 40,000 से अधिक निर्धन परिवारों को पक्के घर बनाने के लिए उनके बैंक खातों में धनराशि प्राप्त हुई है, जिनमें से अधिकतर दलित, महादलित और पिछड़े समुदायों से हैं।

बिहार की प्रगति का श्रेय राज्य की माताओं और बहनों की शक्ति तथा दृढ़ संकल्प को देते हुए श्री मोदी ने कहा कि बिहार की महिलाएं अपनी सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम के महत्व को भली-भांति समझती हैं। उन्होंने जन-धन खाते खोलने के लिए शुरू किए गए व्यापक अभियान का उल्लेख किया, जिससे महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। बिहार में अब लगभग 3.5 करोड़ महिलाओं के जन-धन खाते हैं। श्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकारी योजनाओं का धन अब सीधे इन खातों में स्थानांतरित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा माताओं के लिए मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले डेढ़ महीने में ही बिहार में 24,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्राप्त हुई है, जिसका श्रेय माताओं और बहनों के जन धन खातों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सशक्तीकरण को दिया जा सकता है।

बिहार में 20 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और अकेले चम्पारण में 80,000 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर इस मुकाम तक पहुंची हैं

बिहार में 20 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी

महिला सशक्तीकरण पहलों के प्रभावशाली परिणामों को रेखांकित करते हुए और देशभर तथा बिहार में 'लखपति दीदियों' की बढ़ती संख्या का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाना है और अब तक 1.5 करोड़ महिलाओं ने यह उपलब्धि अर्जित कर ली है। उन्होंने कहा कि बिहार में 20 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और अकेले चम्पारण में 80,000 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर इस मुकाम तक पहुंची हैं। श्री मोदी ने नारी शक्ति को मज़बूत करने के उद्देश्य से सामुदायिक निवेश कोष के रूप में 400 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। उन्होंने श्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई 'जीविका दीदी' योजना की प्रशंसा की, जिसने बिहार की लाखों महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त किया है।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में पहली बार रोजगार की आकांक्षा रखने वालों की सहायता के लिए एक बड़ी योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत किसी निजी कंपनी में पहली नियुक्ति पाने वाले युवाओं को केंद्र सरकार द्वारा 15,000 रुपये दिए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि यह योजना 1 अगस्त से लागू होगी और इस पर केंद्र द्वारा एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल से बिहार के युवाओं को अत्यधिक लाभ होगा।

श्री मोदी ने मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से बिहार में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों में ही बिहार में मुद्रा योजना के तहत लाखों ऋण वितरित किए गए हैं। श्री मोदी ने बताया कि विशेष रूप से चम्पारण में 60,000 युवाओं को अपने स्वरोज़गार उपक्रमों को समर्थन देने के लिए मुद्रा ऋण प्राप्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में नक्सलवाद के विरुद्ध की गई निर्णायक कार्रवाई पर प्रकाश डाला, जिससे बिहार के युवाओं को अत्यधिक लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि चम्पारण, औरंगाबाद, गया और जमुई जैसे ज़िले, जो कभी माओवादी प्रभाव से घिरे थे, अब वहां उग्रवाद में कमी दिख रही है। श्री मोदी ने कहा कि कभी माओवादी हिंसा से घिरे इलाकों में युवा अब बड़े सपने देख रहे हैं। उन्होंने भारत को नक्सलवाद के शिकंजे से पूरी तरह मुक्त कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

'नया भारत' जो शत्रुओं को दंड देने में कोई कसर नहीं छोड़ता

श्री मोदी ने कहा कि यह एक नया भारत है– एक ऐसा भारत जो शत्रुओं को दंड देने में कोई कसर नहीं छोड़ता, ज़मीन और आसमान, दोनों ओर से सैन्य प्रहार करता है। उन्होंने याद दिलाया कि बिहार की धरती से ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि आज उस ऑपरेशन की सफलता पूरी दुनिया देख रही है।

किसानों की उपज और आय बढ़ाने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अकेले मोतिहारी में ही 5 लाख से ज़्यादा किसानों को इस योजना के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्राप्त हुई।

इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी, श्री गिरिराज सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री चिराग पासवान, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री नित्यानंद राय, श्री सतीश चंद्र दुबे, डॉ. राज भूषण चौधरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ■

जनसभा, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)

'भाजपा समृद्ध और विकसित पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जुलाई, 2025 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत' बनाने में पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। भाजपा समृद्ध और विकसित पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। यहां की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरेगी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई रफ्तार पकड़ लेगा। श्री मोदी ने कहा कि आसपास के राज्यों को देखिए। आज असम तेज गति से प्रगति कर रहा है। भाजपा सरकार त्रिपुरा को भी विकास की नई रफ्तार दे रही है। ओडिशा में भी भाजपा सरकार बनने के बाद यह प्रदेश जल्द ही देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में अपनी जगह बना लेगा। इसलिए, पश्चिम बंगाल में आप भी एक बार भाजपा को अवसर देकर एक ऐसी सरकार बनाएं...जो ईमानदार हो, कामदार हो और दमदार हो।

टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरेगी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई रफ्तार पकड़ लेगा

पश्चिम बंगाल को प्रेरणाओं से भरा हुआ बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशभर से लोग यहां रोजगार के लिए आते थे, जबकि आज स्थिति पूरी तरह उलट गई है। यहां नए उद्योग लगने के बजाय, जो हैं उसमें भी ताले लग रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। हमें बंगाल को इस बुरे दौर से बाहर निकालना है। आज जो परियोजनाएं यहां शुरू हुई हैं...वो इसी का प्रतीक हैं। बंगाल बदलाव और विकास चाहता है। बंगाल के उद्योगों को भी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। दुर्गापुर-कोलकाता गैस पाइपलाइन से यहां के उद्योगों को नया जीवनदान मिलेगा। इसीलिए इस पर केंद्र की भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इससे बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे।

पश्चिम बंगाल की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने आश्वस्त किया कि इसे बदला जा सकता है। भाजपा सरकार आने के कुछ ही समय बाद पश्चिम बंगाल, देश के टॉप इंडस्ट्रियल राज्यों में से एक बन सकता है। लेकिन जब तक यहां टीएमसी सरकार रहेगी... ये कभी भी बंगाल के पुराने गौरव को वापस नहीं लाने देगी। क्योंकि इसकी नीतियां निवेश और नौकरी विरोधी हैं। टीएमसी ने बंगाल के नौजवानों के वर्तमान और भविष्य...दोनों को संकट में डाल दिया है। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां की सरकार, नीतियां ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। इसलिए बंगाल का हाल बेहाल हो गया है और आज हर कोई कह रहा है...टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ!

श्री मोदी ने राज्य सरकार की नीतियों पर चोट करते हुए कहा कि मां, माटी, मानुष की बात करने वाली सरकार में हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो पीड़ा और आक्रोश से भर देता है। आज पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। जब यहां डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। इस घटना से देश अभी बाहर भी नहीं निकला था कि एक और कॉलेज में एक बेटी के साथ भयंकर अत्याचार किया गया। इसमें भी जो आरोपी हैं, उनका कनेक्शन टीएमसी से निकला है। टीएमसी के बड़े नेता, मंत्री आरोपियों के बजाय, पीड़ित को ही दोषी ठहराते रहे। ऐसे कई उदाहरण हैं, जो टीएमसी की निर्ममता के साक्षी हैं। हमें मिलकर बंगाल को इस निर्ममता से मुक्ति दिलानी है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने भाजपा की वैचारिक नींव को अपने खून से सींचा है। डॉ. मुखर्जी ने एक देश एक संविधान का जो सपना देखा, वही भाजपा का संकल्प बना और उसे हमने पूरा करके भी दिखाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ही है, जो बांग्ला भाषा को प्रेरणा, परंपरा और पहचान का माध्यम मानती है। तभी तो बीजेपी की केंद्र सरकार ने बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय-सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ किसी भी साजिश को भाजपा कामयाब नहीं होने देगी। ये मोदी की गारंटी है।

श्री मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि पश्चिम बंगाल

को भाजपा की डबल इंजन की सरकार की जरूरत है, ताकि गरीब और आदिवासी कल्याण की जो योजनाएं देशभर में लागू हैं, उनका लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिले। टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को या तो रोक लेती है या फिर उनमें भ्रष्टाचार करती है। रोड, रेल, टेलीकॉम से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट यहां लटके हुए हैं। देश में कई राज्य ऐसे हैं, जहां हर घर में नल लग चुका है। लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्य से एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहां शत-प्रतिशत नल से जल पहुंचा हो। देश में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिल चुके हैं, लेकिन यहां लाखों गरीबों को पक्के घर नहीं मिल पा रहे। इसी तरह 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम पूरे देश में चल रही है। लेकिन टीएमसी निर्ममता के साथ यहां इसे लागू नहीं कर रही। यहां भाजपा सरकार बनते ही इन सभी योजनाओं का फायदा पश्चिम बंगाल के हर परिवार को मिलेगा...ये मोदी की गारंटी है।

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,400 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस्पात नगरी के रूप में विख्यात दुर्गापुर भारत की श्रम शक्ति का एक प्रमुख केंद्र भी है। उन्होंने भारत के विकास में इसके महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन इस भूमिका को और सशक्त करने का अवसर है। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि आज शुरू की गई परियोजनाएं क्षेत्र में संपर्क को बेहतर बनाएंगी, गैस-आधारित परिवहन और गैस-आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देंगी और दुर्गापुर की इस्पात नगरी के रूप में पहचान को और मज़बूत करेंगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं और पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगी। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोज़गार के अनेक नए अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने इन विकास परियोजनाओं के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं।

गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक बने पक्के घर

श्री मोदी ने कहा कि आज वैश्विक चर्चा भारत के विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के इर्द-गिर्द घूम रही है। उन्होंने इसका श्रेय भारत में हो रहे परिवर्तनकारी बदलावों को दिया, जो एक 'विकसित भारत' की नींव रख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि इन बदलावों का एक बड़ा पहलू सामाजिक, भौतिक और डिजिटल सहित बुनियादी ढांचा है। श्री मोदी ने प्रमुख उपलब्धियों जैसे गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक पक्के घर, करोड़ों शौचालय, 12 करोड़ से अधिक नल के पानी के कनेक्शन, हज़ारों किलोमीटर नई सड़कें और राजमार्ग, नई रेल लाइनें, छोटे शहरों में हवाई अड्डे और हर गांव और घर तक व्यापक इंटरनेट पहुंच पर प्रकाश डाला।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस आधुनिक बुनियादी ढांचे का लाभ पश्चिम बंगाल सहित हर राज्य को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में रेल संपर्क में अभूतपूर्व प्रगति का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि बंगाल बड़ी संख्या में वंदे भारत रेलगाड़ियों का संचालन करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। उन्होंने कोलकाता मेट्रो के तेज़ी से विस्तार और नई रेल लाइन पटरियों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण पर चल रहे कार्यों पर प्रकाश डाला।

श्री मोदी ने बताया कि कई रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और बड़ी संख्या में रेलवे ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि आज पश्चिम बंगाल में दो और रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इन सभी प्रयासों से बंगाल के लोगों का जीवन काफी आसान हो जाएगा।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस क्षेत्र के हवाई अड्डे को उड़ान योजना के साथ एकीकृत किया गया है। श्री मोदी ने बताया कि पिछले वर्ष में ही 5 लाख से अधिक यात्रियों ने उड़ान योजना सुविधा के माध्यम से यात्रा की है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस तरह का बुनियादी ढांचा न केवल सुविधा बढ़ाता है, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का उत्पादन भी पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है।

गैस कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व प्रगति

प्रधानमंत्री ने यह रेखांकित किया कि पिछले 10-11 वर्षों में भारत ने गैस कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि इस दशक के दौरान एलपीजी देश भर के घरों तक पहुंच गई है, जिसे वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। उन्होंने 'वन नेशन, वन गैस ग्रिड' दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के शुभारंभ पर सरकार के काम पर बल दिया। इस पहल के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सहित छह पूर्वी राज्यों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है।

श्री मोदी ने कहा कि चाहे भारत के कारखाने हों या खेत, हर प्रयास एक ही संकल्प से प्रेरित है— भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने सरकार के भविष्य का मार्ग— विकास के माध्यम से सशक्तीकरण, रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता के माध्यम से सुशासन को रेखांकित किया। श्री मोदी ने यह कहते हुए अपने संबोधन का समापन किया कि इन मूल्यों को कायम रखते हुए पश्चिम बंगाल को भारत की विकास यात्रा का एक मजबूत इंजन बनाया जाएगा।

इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस, केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री शांतनु ठाकुर और डॉ. सुकांत मजूमदार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ■

रिपोर्ट

जनता के हाथों में शक्ति

भारत में सहकारी समितियों की त्वरित उन्नति और उनमें हो रहे बदलाव

"भारत के लिए सहकारी समितियां संस्कृति का आधार हैं, जीवन शैली हैं। भारत अपनी भावी प्रगति में सहकारी समितियों की बड़ी भूमिका देखता है।"
—प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारत अपनी सहकारिता की संस्कृति के पुनरुत्थान का साक्षी बन रहा है, जिसमें जमीनी स्तर की समितियां सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और समावेशी विकास के शक्तिशाली इंजन के रूप में उभर रही हैं। भारत में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी शक्ति का उल्लेखनीय उदाहरण राजस्थान की बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति है। वर्ष 1954 में केवल 15 सदस्यों और मात्र 30 रुपये के शेयर के साथ स्थापित यह समिति आज 8,299 से अधिक सदस्यों और 107.54 लाख रुपये के शेयर के साथ एक संपन्न समिति के रूप में विकसित हो चुकी है, जिनमें से 70 प्रतिशत से अधिक हाशिए के समुदायों से हैं। बीते दशकों में यह कृषि के मूलभूत स्वरूप से आगे बढ़ते हुए काफी विकसित हो चुकी है। अब यह तीन शाखाओं के साथ एक मिनी बैंक का संचालन करती है और अकेले 2018-19 में इसने 4.55 करोड़ रुपये की जमा राशि जुटाई। इसका ई-मित्र प्लस सेंटर बीमा और आधार-लिंक्ड सुविधाओं से लेकर जाति और आय प्रमाण पत्र और उपयोगिता बिल भुगतान तक की महत्वपूर्ण नागरिक सेवाएं प्रदान करता है। इस सहकारी समिति को एनसीडीसी राष्ट्रीय सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कार (2010) और एनसीडीसी क्षेत्रीय पुरस्कार (2018) से सम्मानित किया जा चुका है। यह बदलाव कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि यह सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की एक राष्ट्रव्यापी मुहिम का हिस्सा है

वर्तमान में भारत में 8.44 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जो ऋण, आवास, विपणन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि सहित 30 क्षेत्रों में फैली हैं और ग्रामीण ऋण, स्वरोजगार और सामूहिक आर्थिक मजबूती की दिशा में आवश्यक साधन के तौर पर कार्य कर रही हैं। सहकारी समितियों की मुख्य बातें निम्न हैं:

- भारत में 30 क्षेत्रों में 8.44 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जो ग्रामीण ऋण, रोज़गार और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रही हैं।
- सहकारी समितियों को कुशल, डिजिटल और आपदा-प्रतिरोधी समितियों में बदलने के लिए 22 जुलाई, 2025 तक 73,492 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है और 59,920 पीएसीएस को एकीकृत ईआरपी प्लेटफ़ॉर्म पर जोड़ा गया है।
- एक ही प्लेटफ़ॉर्म से विविध ग्रामीण सेवाएं प्रदान करने के लिए 22 जुलाई, 2025 तक 23,173 नई बहुउद्देशीय पीएसीएस, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं।
- जेम पर 667 सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में पंजीकृत किया गया है और 31 मार्च, 2025 तक सहकारी समितियों द्वारा 319.02 करोड़ रुपये के 2,986 लेनदेन हुए हैं।

✦ भारत में 30 क्षेत्रों में 8.44 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जो ग्रामीण ऋण, रोज़गार और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रही हैं

✦ जेम पर 667 सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में पंजीकृत किया गया है और 31 मार्च, 2025 तक सहकारी समितियों द्वारा 319.02 करोड़ रुपये के 2,986 लेनदेन हुए हैं

- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) ने 8,863 पीएसीएस/सहकारी समितियों को शामिल किया है, जिनके माध्यम से 27 देशों को 5,239.5 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि वस्तुओं का सफलतापूर्वक निर्यात किया गया है।

उल्लेखनीय है कि साबरकांठा की बाल गोपाल बचत एवं ऋण सहकारी समिति भारत की एकमात्र ऐसी सहकारी समिति है, जो विशेष रूप से 0-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। इस अनूठे 'बाल बचत संस्कार' मॉडल के माध्यम से बच्चों को सेविंग बॉक्स दिए जाते हैं और उनमें जमा हुई राशि हर महीने उनके बैंक खातों में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर जमा की जाती है। मार्च, 2024 तक 335 गांवों के 19,020 बाल सदस्यों ने 17.47 करोड़ रुपये की बचत की है। यह सहकारी समिति सदस्य बच्चे के अभिभावक को स्व-गारंटीकृत ऋण और बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए संपत्ति पर ऋण भी प्रदान करती है। कुल 1,070 बच्चों के अभिभावकों को ऋण दिए गए हैं और कुल 5,370 बच्चों को वित्तीय परामर्श दिया गया है।

2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना

परिवर्तन की यह लहर 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना

के साथ शुरू हुई। मात्र चार वर्षों में इसने सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण करने और उनमें विविधता लाने के लिए 61 सुविचारित पहल शुरू की हैं। सबसे परिवर्तनकारी पहलों में 73,492 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव को मंज़ूरी, 59,920 पीएसीएस को (22 जुलाई, 2025 तक) एकीकृत उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ना और नए उप-नियमों के तहत बहुउद्देशीय सहकारी मॉडलों की औपचारिक शुरुआत शामिल है।

सरकार की रणनीति में बड़े पैमाने का विस्तार भी शामिल है। 22 जुलाई, 2025 तक 23,173 नई बहुउद्देशीय पीएसीएस, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां पंजीकृत हो चुकी हैं। इन पीएसीएस को एकल ईआरपी-आधारित डिजिटल आर्किटेक्चर के आधार पर अनाज भंडारण, उर्वरक और बीज वितरण, एलपीजी और पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्रों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है।

667 सहकारी समितियां सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर खरीदार के रूप में पंजीकृत

यह डिजिटल बदलाव केवल वित्त तक ही सीमित नहीं है। 31 मार्च, 2025 तक 667 सहकारी समितियां सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर खरीदार के रूप में पंजीकृत हो चुकी थीं। राष्ट्रीय बाज़ारों तक ग्रामीण कारीगरों की पहुंच बढ़ाने के लिए इन सहकारी समितियों को विक्रेता के रूप में भी शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 31 मार्च, 2025 तक इन सहकारी समितियों द्वारा 319.02 करोड़ रुपये के 2,986 लेनदेन हो चुके थे।

भारत में सहकारी समितियां तेज़ी से स्थानीय सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम कर रही हैं, जो वित्तीय सेवाओं, शैक्षिक विकास, कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और आवश्यक उपयोगिताओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करती हैं, जिससे जमीनी स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।

भारत के सहकारी सुधारों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी आकार लिया है। सहकारी समितियों को बाज़ारों तक पहुंच, ब्रांडिंग और निर्यात क्षमता प्रदान करने के लिए 2023 में तीन बहु-राज्य सहकारी समितियों का गठन किया गयाः

- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल)
- राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल)
- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल)

31 मार्च 2025 तक एनसीईएल ने सामूहिक निर्यात की सुविधा के लिए पहले ही 8,863 पीएसीएस/सहकारी समितियों को शामिल कर लिया है। इसके अलावा, एनसीईएल ने चावल, गेहूं, मक्का, चीनी, प्याज और जीरा सहित लगभग 13.08 एलएमटी कृषि वस्तुओं का सफलतापूर्वक निर्यात किया है, जिनका मूल्य 27 देशों में 5,239.5 करोड़ रुपये है। यद्यपि 5,185 पीएसीएस/सहकारी समितियां एनसीओएल की सदस्य बन गई हैं। एनसीओएल ने 'भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड' के तहत लगभग 167.1 लाख रुपये के 21 उत्पाद लॉन्च किए हैं। एनसीओएल ने 10 राज्यों में नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी ओर 19,171 पीएसीएस/सहकारी समितियां बीबीएसएसएल की सदस्य बन गई हैं। बीबीएसएसएल को 13 राज्यों में बीज लाइसेंस प्रदान किया गया है।

मंत्रालय ने इस परिवर्तन को और तेज़ करने के लिए हाल ही में 24 जुलाई, 2025 को एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति शुरू की है। राष्ट्रीय सहकारी नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को समावेशी बनाना, उन्हें पेशेवर रूप से प्रबंधित करना, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना और विशेष रूप से ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर रोज़गार और आजीविका के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाना है। नई सहकारी नीति 2025-45 तक यानी अगले दो दशकों के लिए भारत के सहकारी आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगी। नई नीति 'सहकार-से-समृद्धि' के विज़न को प्राप्त करने का रोडमैप तैयार करेगी और 2047 तक भारत के 'आत्मनिर्भर' और 'विकसित' बनने की सामूहिक महत्वाकांक्षा में योगदान देगी।

भारत में सहकारी समितियां तेज़ी से स्थानीय सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम कर रही हैं, जो वित्तीय सेवाओं, शैक्षिक विकास, कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और आवश्यक उपयोगिताओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करती हैं, जिससे जमीनी स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय सहकारी समितियों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। यह योजना अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सर्वोत्तम प्रथाओं के दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल पहुंच के माध्यम से भारत के सफल सहकारी मॉडलों जैसे अमूल, इफको और कृभको को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सरकार सहकारी निर्यात को बढ़ावा देने, सहकारी समितियों के भीतर स्टार्टअप्स को समर्थन देने और देशव्यापी शिक्षा को सुगम बनाने के लिए भी काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य भारत की जमीनी ताकत और विशाल सदस्यता आधार का लाभ उठाकर सहकारी नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है।

भारत में सहकारी समितियों की त्वरित उन्नति अब कोई काल्पनिक आदर्श नहीं रह गया है, यह एक जमीनी, मूलभूत क्रांति है। सहकारी समितियां न केवल लोगों को सशक्त बना रही हैं, बल्कि वे समावेशी, लोकतांत्रिक विकास की नए सिरे से परिकल्पना भी कर रही हैं। एक सदी पहले एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुई यह मुहिम अब भारत के न्यायसंगत और समावेशी विकास की कुंजी बन सकती है। ■

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को दी मंज़ूरी

100 ज़िलों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास को तेज़ गति मिलेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई को छह वर्ष की अवधि के लिए 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को स्वीकृति दे दी। यह योजना 2025-26 से 100 ज़िलों में लागू होगी। नीति आयोग के आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम से प्रेरित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है।

योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी, फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, कटाई के बाद पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधा में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण उपलब्धता सुगम बनाना है। यह 2025-26 के केंद्रीय बजट में 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' के अंतर्गत 100 ज़िले विकसित किये जाने की घोषणा के अनुरूप है। योजना का क्रियान्वयन 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्यों की अन्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदारी में किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी, फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, कटाई के बाद पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधा में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण उपलब्धता सुगम बनाना है

तीन प्रमुख संकेतकों— कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और अल्प ऋण वितरण के आधार पर सौ जिले चिन्हित किये जाएंगे। प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में जिलों की संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र (वह कुल क्षेत्रफल, जहां किसी कृषि वर्ष में वास्तव में फसलें उगाई जाती हैं) और परिचालन जोत के हिस्से पर आधारित होगी। इस योजना में प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले का चयन किया जाएगा।

योजना के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। जिला धन धान्य समिति द्वारा जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधि योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। समिति में प्रगतिशील किसान भी सदस्य होंगे। जिले की योजनाएं फसल विविधीकरण, जल एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को विस्तार देने जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगी।

प्रत्येक धन धान्य जिले में योजना में प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतकों के अनुसार की जाएगी। नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी भी नियमित आधार पर योजना की समीक्षा करेंगे।

इन सौ जिलों में लक्षित परिणामों में सुधार के साथ देश के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के मुकाबले समग्र औसत में वृद्धि होगी। योजना के परिणामस्वरूप उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में मूल्यवर्धन (उत्पाद और सेवा में उन्नयन) होगा और स्थानीय आजीविका सृजित होगी। इस प्रकार इस योजना से घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) हासिल होगी। इन सौ जिलों के संकेतकों में उत्तरोत्तर सुधार के साथ ही राष्ट्रीय संकेतकों में भी स्वतः ही वृद्धि होगी। ■

कोयले के आयात में भारी कमी के कारण वित्त वर्ष 2024-2025 में लगभग 60,681.67 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कुल 243.62 मिलियन टन (एमटी) कोयले का आयात हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 264.53 मिलियन टन था। कोयले के आयात में लगभग 20.91 मिलियन टन की कमी के कारण वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-2025 में लगभग 60,681.67 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 21 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन/आपूर्ति से पूरी होती है। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2029-30 तक लगभग 1.5 बिलियन टन के घरेलू कोयला उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और गैर-ज़रूरी कोयला आयात में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2029-30 तक कोयला उत्पादन में वृद्धि के अनुमान को ध्यान में रखते हुए देश में सक्षम कोयला निकासी के लिये बुनियादी ढांचे विकसित करने के लिए फरवरी, 2024 में कोयला लॉजिस्टिक योजना और नीति आरंभ की है। ■

बीमा सखी योजना में 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं का नामांकन

भारत सरकार ने 9 दिसंबर, 2024 को बीमा सखी- 'महिला कैरियर एजेंट (एमसीए) योजना' शुरू की। एलआईसी ने वित्त वर्ष 2024-25 में बीमा सखियों को 62.36 करोड़ रुपये वजीफे के रूप में दिए हैं। चालू वित्त वर्ष (2025-26) में एलआईसी ने इस योजना के लिए 520 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया है, जिसमें से 14.7.2025 तक 115.13 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में देश में 2,05,896 बीमा सखियां हैं। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने 21 जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

एलआईसी बीमा सखियों को उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से अवसर प्रदान करती है। स्नातक बीमा सखियां 5 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर एलआईसी के प्रशिक्षु विकास अधिकारी के पद हेतु भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं।

उपरोक्त के अलावा, एलआईसी बीमा सखियों को उनकी नियुक्ति के बाद पहले तीन वर्षों तक वजीफा देती है ताकि उन्हें जीवन बीमा एजेंसी के रूप में करियर बनाने में मदद मिल सके। यह वजीफा योजना उनके कमीशन भुगतान के अतिरिक्त है और कुछ निश्चित प्रदर्शन मानदंडों पर निर्भर करती है। वजीफे की राशि पहले वर्ष में 7000 रुपये प्रति माह से लेकर तीसरे वर्ष में 5000 रुपये प्रति माह तक होती है। ■

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मई, 2025 तक कुल 20.06 लाख सदस्यों का बनाया रिकॉर्ड

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मई, 2025 के लिए अनंतिम पेरोल डेटा जारी किया है जिसमें अप्रैल, 2018 में पेरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से 20.06 लाख सदस्यों के साथ अब तक सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़ा पिछले महीने अप्रैल, 2025 की तुलना में वर्तमान में पेरोल परिवर्धन में 4.79 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

इसके अलावा, वर्ष-दर-वर्ष विश्लेषण ईपीएफओ की प्रभावी पहुंच के परिणामस्वरूप मई, 2024 की तुलना में शुद्ध वेतन वृद्धि में 2.84 प्रतिशत की वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ईपीएफओ से मई, 2025 में लगभग 9.42 लाख नए सदस्यों जुड़े हैं जो अप्रैल, 2025 की तुलना में 11.04 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। नए सदस्यों की संख्या में यह वृद्धि बढ़ते रोजगार के अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ के सफल आउटरीच कार्यक्रमों का परिणाम है।

ईपीएफओ ने 18-25 आयु वर्ग के 5.60 लाख नए सदस्य जोड़े, जो मई 2025 में जुड़े कुल नए सदस्यों का 59.48 प्रतिशत है। इस महीने में जुड़े 18-25 आयु वर्ग के नए सदस्यों की संख्या पिछले महीने अप्रैल, 2025 की तुलना में 14.53 प्रतिशत अधिक है।

इसके अतिरिक्त मई, 2025 के लिए 18-25 आयु वर्ग के लिए शुद्ध पेरोल वृद्धि लगभग 8.73 लाख है, जो अप्रैल 2025 के पिछले महीने से 15.10 प्रतिशत की वृद्धि और मई, 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में 0.11 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। यह वृद्धि दर्शाती है कि पहली बार नौकरी करने वाले और संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा हैं। ■

मानसून सत्र के पहले दिन 'बिल्स ऑफ लैडिंग, 2025' विधेयक पारित

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को राज्यसभा ने 'बिल्स ऑफ लैडिंग, 2025' विधेयक पारित कर दिया, जिससे इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्ल्यू) श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 21 जुलाई को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया यह विधेयक भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी पल है।

इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका था। अब यह विधेयक कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अधिनियमित होने के बाद यह भारत में समुद्री नौवहन दस्तावेज़ीकरण के लिए 169 वर्ष पुराने औपनिवेशिक काल के भारतीय लैडिंग अधिनियम, 1856 की जगह एक आधुनिक, सरलीकृत और वैश्विक रूप से संरेखित कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। ■

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और एनएचएम के तहत 10.18 करोड़ महिलाओं की सर्विकल कैंसर की जांच की गई

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में 30 वर्ष और उससे अधिक आयु की 10.18 करोड़ से अधिक महिलाओं की गर्भाशय ग्रीवा (सर्विकल) कैंसर की जांच की, जो महिला स्वास्थ्य क्षेत्र में मंत्रालय की एक बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के माध्यम से गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की जांच, रोकथाम और प्रबंधन हेतु जनसंख्या-आधारित पहल का हिस्सा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने 25 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

इस पहल में 30 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा एएएम के अंतर्गत उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्य रूप से एसिटिक एसिड (वीआईए) के साथ दृश्य निरीक्षण का उपयोग करके स्क्रीनिंग की जाती है। वीआईए पॉजिटिव मामलों को आगे के नैदानिक मूल्यांकन के लिए उच्च केंद्रों में भेजा जाता है।

इसमें जमीनी स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो जोखिमग्रस्त लोगों की पहचान करते हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग में उनकी भागीदारी को सुगम बनाते हैं। इसके लिए वे समुदाय आधारित मूल्यांकन जांच सूची (सीबीएसी) प्रपत्रों का उपयोग करते हैं। आशा कार्यकर्ता शीघ्र पहचान और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में भी मदद करते हैं।

सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियों को बढ़ावा देना और लक्षित संचार अभियान कैंसर नियंत्रण के निवारक पहलू को और मज़बूत बनाते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और विश्व कैंसर दिवस जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग सर्विकल कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों पर निरंतर जन सहभागिता सुनिश्चित करता है।

एनएचएम के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार जागरूकता सृजन गतिविधियों के लिए समर्पित निधियां प्रदान की जाती हैं।

मंत्रालय ने 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की स्क्रीनिंग में तेज़ी लाने के लिए 20 फ़रवरी से 31 मार्च, 2025 तक एक समयबद्ध एनसीडी स्क्रीनिंग अभियान भी शुरू किया था। इस अभियान की सफलता ने वर्तमान उपलब्धि में योगदान दिया है।

20 जुलाई, 2025 तक राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल के आंकड़ों से पता चलता है कि 30 वर्ष और उससे अधिक आयु की 25.42 करोड़ महिलाओं की पात्र आबादी में से 10.18 करोड़ महिलाओं की गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए जांच की गई है। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से व्यापक और निवारक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ■

कमल पुष्प — सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

हरिशंकर तिवारी

स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी ने 1957 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। छात्र जीवन में वह भारतीय जनसंघ के सक्रिय सदस्य एवं कार्यकर्ता रहे। उस दौरान श्री तिवारी गांव-गांव जाकर जनसंघ को मजबूत करने के कार्य में लगे रहे। उन्होंने आपातकाल के दौरान भूमिगत आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पश्चिम चंपारण के रामनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई और अपने जीवन के अंतिम दिनों तक पार्टी के साथ जुड़े रहे तथा कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते रहे। 23 जून, 2015 को उनका निधन हो गया। ■

स्व.हरिशंकर तिवारी

जन्मतिथि
17/06/1932

राज्य
बिहार

जिला
पश्चिम चंपारण

शहर
रामनगर, बेतिया

दायित्व
जिला कार्यकारिणी सदस्य

सक्रिय वर्ष
1956-2004

'भारत का टाइगर हिल है, भारत का टाइगर हिल रहेगा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कारगिल युद्ध में विजय व अपने शौर्य का परचम लहराने वाले और अपनी जान की बाजी लगाने वाले देश के वीर जवानों एवं शहीदों को नमन किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्री नड्डा ने कहा कि देश की रक्षा में सेना के शौर्य के साथ नीति निर्धारकों की भूमिका भी अहम रहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर कर यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए भारत दुश्मन के घर में घुसकर कार्रवाई करेगा और यही नए भारत का न्यू नॉर्मल है। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉ. सुधा यादव, कर्नल वीएन थापर, लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी, लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. खंडारे एवं लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भारत ने साधारण नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जैश और लश्कर के मुख्यालय ध्वस्त कर दिए

श्री नड्डा ने कहा कि 26 वर्ष पहले 1999 की फरवरी में कारगिल सेक्टर, द्रास सेक्टर, बटालिक सेक्टर, मस्को सेक्टर और टाइगर हिल पर पाकिस्तान की फौज ने पीठ में छुरा भोंककर कब्जा करने का प्रयास किया था। कारगिल में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेनाओं को उस स्थान को फिर से वापस लेने और वहां तिरंगा झंडा फहराने का आदेश दिया था, साथ ही उन्होंने नारा दिया था, 'भारत का टाइगर हिल है, भारत का टाइगर हिल रहेगा।'

उन्होंने कहा कि वह बहुत ही कठिन लड़ाई थी, क्योंकि टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिकली टाइगर हिल की ऊंचाइयों पर पाकिस्तान की फौज बैठी थी और भारतीय सेना नीचे थी, इसलिए भारतीय सेना एक तकलीफदायक परिस्थितियों में थी और पाकिस्तानी सेना लगातार भारत के नेशनल हाईवे की मूवमेंट्स को देख रही थी। ऐसी परिस्थिति में 'ऑपरेशन विजय' शुरू हुआ। 15,000 फीट की ऊंचाई के साथ-साथ बर्फीली हवाओं, तेज बारिश के बावजूद मां भारती के रणबाकुरों ने यह लड़ाई लड़ी। 81 दिन की लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने इसमें विजय हासिल की और आज, 26 जुलाई को पूरा देश 'ऑपरेशन विजय दिवस' के रूप में मनाता है।

उन्होंने कहा कि उरी की घटना में हमारे 18 जवान शहीद हो गए। उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा था पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। एक समय में भारत 26/11 की तरह डोजियर लेके जाता था, लेकिन अब जमाना बदल चुका था। उरी हमले के कुछ दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के सारे लॉन्चिंग पैड्स को ध्वस्त कर दिया। उसी तरह, पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान जैश-ए-मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर की गाड़ी से हुए हमले में शहीद हो गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा, "बहुत जल्द इसका जवाब मिलेगा" और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मधुबनी से पूरे विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया था कि जिस तरह की घटना घटी है, पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान को कल्पना से अधिक करारा जवाब मिलेगा। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने बहावलपुर, मुरीदके, नूरखान, सियालकोट, रफीकी, चकलाला और रहीम यार खान में पाकिस्तान के भीतर घुसकर मिसाइल स्ट्राइक की। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, ठीक वैसे ही भारतीय सेना ने घर में घुसकर जवाब दिया। भारत ने साधारण नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जैश और लश्कर के मुख्यालय ध्वस्त कर दिए। भारत ने यह दिखा दिया कि यह नया भारत है, यह भारत का न्यू नॉर्मल है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए सिविलियन एयरक्राफ्ट चलाता रहा, लेकिन उनकी हर मिसाइल को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह नाकामयाब कर दिया। 9 और 10 मई को भारत ने तीन घंटे में पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जिसमें नूर खान, रफीक़ी, मुरीदके, सुक्कुर, सियालकोट, सरगोधा, बुलारी, जकोबाबाद शामिल थे। ■

विरासत का हस्तांतरण: मोदी जी ने वाजपेयी जी के 'विकसित भारत' के स्वप्न को कैसे साकार किया

डॉ. के. लक्ष्मण

'नेतृत्व' अगर संक्षेप में समझा जाए, तो उसकी परिभाषा उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि उस विरासत से होती है जो वह दूसरों को देता है। एक सच्चा नेता वह होता है जिसके कार्य एक ऐसी विरासत छोड़ते हैं जो दूसरों को बड़े सपने देखने, सीखने एवं अधिक हासिल करने और एक बेहतर, समग्र व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए भी काम करता है। भारत में ऐसे कई महान नेता हुए हैं, लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस आदर्श के प्रतीक के रूप एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। उन्हें अक्सर 'अजातशत्रु' कहा जाता था, जिसका कोई शत्रु न हो।

राजनीति, शासन और समावेशी विकास के उनके विचारों ने मेरी पीढ़ी के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। एक गौरवान्वित सांसद और चार दशकों से भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित सदस्य के रूप में अटल जी के विचारों ने मुझे गहराई से प्रेरित किया है और उनका नेतृत्व मेरे लिए एक मार्गदर्शक रहा है। समावेशिता के उनके विचार अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के आदर्श वाक्य 'सबका साथ, सबका विकास' में समाहित हो गए हैं।

वाजपेयी जी के परिवर्तनकारी विचारों और उनकी नेतृत्व शैली का मुझ पर तब से प्रभाव रहा है जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) के साथ जुड़ा एक युवा कार्यकर्ता था और 1970 के दशक में उस्मानिया विश्वविद्यालय से अपनी राजनीतिक सक्रियता शुरू की थी।

इसके बाद, जब मैं 1980 के दशक में भाजपा में शामिल हुआ और जमीनी स्तर पर काम करने के साथ-साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग करने लगा, तो वाजपेयी जी के आदर्शों ने मेरी मूल्य-पद्धति को गहराई से आकार दिया और मेरे कार्यों को आगे बढ़ाया। वह न केवल मेरे लिए, बल्कि मेरे साथियों के लिए भी एक मार्गदर्शक रहे हैं।

मुझे न केवल वाजपेयी जी के साथ, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं परिवर्तनकारी नेतृत्व में भी काम करने का अनूठा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अटल जी के विचारों को गहराई से अपनाया है। यह लेख इन महान व्यक्तित्वों के प्रति एक श्रद्धांजलि है; यह मेरा हार्दिक समर्पण है जो मेरे व्यक्तिगत संवादों, मेरे अनुभवों और उन विचारों को समेटने का प्रयास करता है कि कैसे अटल जी के विचार, जिन्होंने एक पीढ़ी को प्रेरित किया, अब मोदी जी के नेतृत्व में फलित हो रहे हैं, जिन्होंने उस दृष्टिकोण को पुनर्जीवित और 'नए भारत' के रूप में इस विचार को विस्तारित किया है।

> एक सच्चा नेता वह होता है जिसके कार्य एक ऐसी विरासत छोड़ते हैं जो दूसरों को बड़े सपने देखने, सीखने एवं अधिक हासिल करने और एक बेहतर, समग्र व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए भी काम करता है। भारत में ऐसे कई महान नेता हुए हैं, लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस आदर्श के प्रतीक के रूप एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। उन्हें अक्सर 'अजातशत्रु' कहा जाता था, जिसका कोई शत्रु न हो

वाजपेयी जी के विचार एवं विरासत

अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल एक पार्टी के नेता या राष्ट्र के प्रधानमंत्री ही नहीं थे, वह एक ऐसे राजनेता थे जिनके व्यक्तित्व में बौद्धिक गहराई, काव्यात्मक संवेदनशीलता और भारतीय लोकाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का मिश्रण झलकता था।

अटल जी के कई भाषण, जो उनके विशिष्ट शायराना अंदाज में अद्वितीय वाक्पटुता और काव्यात्मक शैली में दिए गए थे, आज भी युवा पीढ़ी के बीच सुने जाते हैं और उन्हें एक किंवदंती बना देते हैं। एक भाषण में, जब उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उन्होंने कहा था, "सरकार तो आएगी और जाएगी, यह देश रहना चाहिए।" यह भाषण राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

इस दृढ़ संकल्प की झलक भारत की वर्तमान विदेश नीति में देखी जा सकती है, जिसे मोदी जी 'भारत प्रथम' नीति कहते हैं।

अटल जी के भाषणों में देश के आम लोगों के प्रति उनकी गहरी चिंता भी झलकती थी। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी दृष्टि केवल सहानुभूति से कहीं अधिक सहानुभूति और समझदारी पर आधारित थी। वह एक ऐसे लोकतंत्रवादी थे जो संवाद और आम सहमति बनाने में

विश्वास रखते थे और उन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता रखते थे, जिन पर भारत का निर्माण हुआ है।

वाजपेयी जी का दृष्टिकोण: वह विचार जिन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त किया

राष्ट्र के लिए अटल जी का दृष्टिकोण कहीं अधिक व्यापक और दूरगामी था, इसमें कई प्रमुख स्तंभ शामिल हैं जो आज भी भारत के विकास पथ को परिभाषित करते हैं, इनमें शामिल हैं:

समावेशी विकास: 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'

मोदी जी का नारा 'सबका साथ, सबका विकास', वाजपेयी जी के समावेशी विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिन्होंने ऐसी प्रगति का समर्थन किया जहां कोई भी पीछे न छूटे। वाजपेयी जी समावेशी विकास को केवल आर्थिक विकास की रणनीति के रूप में नहीं, बल्कि सत्ताधारी नेताओं की नैतिक अनिवार्यता के रूप में देखते थे।

उनका दृढ़ विश्वास था कि विकास और प्रगति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए, विशेषकर उन लोगों तक जो जाति, वर्ग या किसी अन्य कारण से जन्म से ही सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' सिद्धांत के सच्चे प्रतीक थे, जिसका अर्थ है अंतिम व्यक्ति का उत्थान। प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान जैसी कई पहलों की शुरुआत करके इन विचारों को क्रियान्वित किया। उन्होंने माना कि हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तीकरण और गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए 'शिक्षा' सबसे प्रभावी साधन है। इसलिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था।

अटल जी समझते थे कि राष्ट्रीय प्रगति तभी संभव है जब कोई भी पीछे न छूटे, इसलिए उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं की नींव रखी, जिनका उद्देश्य दूर-दराज के गांवों में रहने वाले और प्रगति के लाभों से वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाना था। उनका दृष्टिकोण दान-पुण्य तक सीमित नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए अवसर पैदा करने और क्षमता निर्माण करने का था। क्योंकि आत्म-सम्मान केवल आत्मनिर्भरता से ही आ सकता है।

बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया

राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम से औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने में मज़बूत बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका की वाजपेयी जी की गहरी समझ ने उन्हें कई बुनियादी ढांचा निर्माण परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। इनमें से सबसे प्रतिष्ठित 'स्वर्णिम चतुर्भुज' परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत के चार सबसे विकसित महानगरों– दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को विश्व स्तरीय राजमार्गों के एक नेटवर्क से जोड़ना था।

यह परियोजना केवल सड़कें या राजमार्ग बनाने के बारे में नहीं थी, बल्कि आर्थिक गलियारे बनाने, यात्रा के समय को कम करने, जिससे व्यापार सुगम होगा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, के बारे में थी। मुझे याद है कि इस परियोजना के विशाल आकार को देखते हुए शुरुआत में इसे लेकर उत्साह और संशय दोनों थे। लेकिन वाजपेयी जी का संकल्प अटल था। उन्होंने इसे भारत को एक आधुनिक आर्थिक महाशक्ति में बदलने की दिशा में एक आधारभूत कदम के रूप में देखा।

अटल बिहारी वाजपेयी दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' सिद्धांत के सच्चे प्रतीक थे, जिसका अर्थ है अंतिम व्यक्ति का उत्थान। प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान जैसी कई पहलों की शुरुआत करके इन विचारों को क्रियान्वित किया। उन्होंने माना कि हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तीकरण और गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए 'शिक्षा' सबसे प्रभावी साधन है। इसलिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था

स्वर्णिम चतुर्भुज के अलावा यह मानते हुए कि ग्रामीण समृद्धि के लिए गांवों को बाज़ारों और सेवाओं से जोड़ना बेहद ज़रूरी है, अटल जी की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। इस दौरान दूरसंचार क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसने आने वाली डिजिटल क्रांति की नींव रखी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में भारत अब दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट और नेटवर्क शुल्क वाले देशों में से एक है।

परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता

संप्रभुता और दृढ़ संकल्प भारतीय गणराज्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया, जो इस तथ्य का स्पष्ट उदाहरण था। यह शायद वाजपेयी जी की राजनीतिक यात्रा के सबसे निर्णायक फैसलों में से एक था, जिसने उनके दूरदर्शी नेतृत्व और आत्मनिर्भरता के प्रति उनके संकल्प को उजागर किया।

पोखरण- द्वितीय परीक्षण, जिसे मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, करने का साहसिक निर्णय, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्ति द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों और बहिष्कार के भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद लिया गया था। अटल जी के लिए, भारत की संप्रभुता ऐसी चीज नहीं है जिससे समझौता किया जा सके। उन्होंने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित किया और इसके परिणामों से अद्भुत धैर्य और कूटनीतिक कुशलता से निपटा।

उन्होंने परमाणु हथियारों के मामले में भारत की 'पहले इस्तेमाल न करने' की दृढ़ नीति दोहराई और साथ ही अपनी सामरिक स्वायत्तता को भी स्पष्ट रूप से स्थापित किया। यह उन क्षणों में से एक था जिसने प्रत्येक भारतीय राष्ट्रवादी के हृदय को अपार राष्ट्रीय गौरव से भर दिया और दुनिया को यह संकेत दिया कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने सिद्धांतों पर, अब और हमेशा, यहां तक कि चुनौती मिलने पर भी अडिग रहेगा।

सुशासन नीति: जन-केंद्रित विकास

अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनकी सरकार सुशासन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध थी। अटल जी लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। उन्होंने एक जटिल गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य आम सहमति बनाना और एक स्थिर प्रशासन बनाए रखना था।

अटल जी ने जन-केंद्रित नीतियों पर ध्यान लगाया और यह सुनिश्चित किया कि सरकारी कार्यक्रम सीधे उन नागरिकों को लाभान्वित करें जिनको इनकी आवश्यकता है। शासन पर उनका ध्यान व्यावहारिक होने के साथ-साथ सिद्धांत-आधारित भी था। उन्होंने हमेशा संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर राष्ट्र कल्याण को प्राथमिकता दी।

अटल जी ने जन-केंद्रित नीतियों पर ध्यान लगाया और यह सुनिश्चित किया कि सरकारी कार्यक्रम सीधे उन नागरिकों को लाभान्वित करें जिनको इनकी आवश्यकता है। शासन पर उनका ध्यान व्यावहारिक होने के साथ-साथ सिद्धांत-आधारित भी था। उन्होंने हमेशा संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर राष्ट्र कल्याण को प्राथमिकता दी

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा: सद्भाव और सहमति की वकालत

भारत जैसे अद्भुत विविधता वाले राष्ट्र में 'विविधता में एकता' का सिद्धांत एक निर्विवाद वास्तविकता है। अटल जी ने अपनी गहन दूरदर्शिता के साथ राष्ट्रीय एकता और सद्भाव का निरंतर समर्थन किया और अक्सर संकीर्ण दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर आम सहमति बनाने के लिए विचार-विमर्श को आगे बढ़ाया।

जटिल जम्मू-कश्मीर मुद्दे के प्रति उनका दृष्टिकोण इस दर्शन का प्रमाण था, जो उनके त्रिपक्षीय दृष्टिकोणः इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत, यानी मानवता, लोकतंत्र और कश्मीर के अनूठे सार में खूबसूरती से समाहित था। यह मार्गदर्शक सिद्धांत जटिल चुनौतियों का समाधान बलपूर्वक करने के बजाय, खुले संवाद और सच्ची सहानुभूति के माध्यम से करने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता था।

वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस गहन सत्य को रेखांकित किया कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में निहित है, जो राष्ट्र के ताने-बाने में गहराई से समाई हुई है। उनका दृढ़ विश्वास था कि सभी हितधारकों और समुदायों के बीच सद्भाव का विकास न केवल वांछनीय है, बल्कि राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। उन्होंने स्वयं को एक ऐसे नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिनमें विपक्ष के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने, असहमति के स्वरों का धैर्यपूर्वक सामना करने और निरंतर साझा आधार तलाशने की अद्भुत क्षमता थी। ऐसा करते हुए उन्होंने संसदीय लोकतंत्र के सार और सच्ची भावना को भी मूर्त रूप दिया।

वाजपेयी जी के साथ मेरे घनिष्ठ संबंध ने मुझे संवाद के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, नेतृत्व में उनकी गहन विनम्रता और एक सशक्त तथा करुणामय भारत में उनके अटूट विश्वास को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि नेतृत्व का अर्थ प्रभुत्व स्थापित करना नहीं, बल्कि सेवा करना है; आदेश देना नहीं, बल्कि विश्वास दिलाना है और व्यक्तिगत गौरव के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई के लिए है...

(जारी है)

(लेखक भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद हैं)

भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर

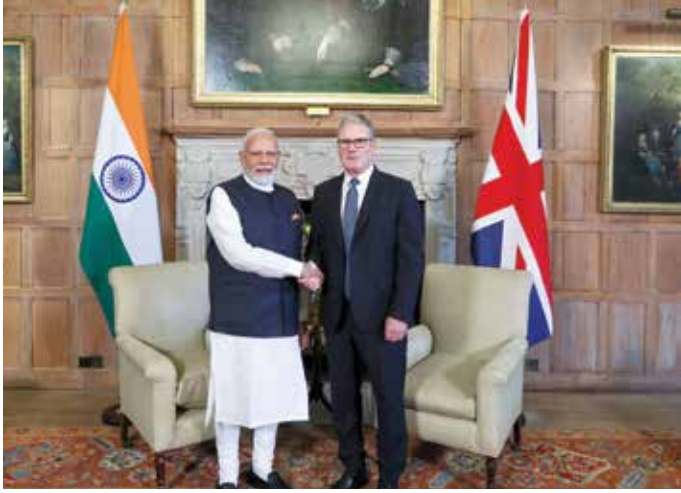

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23-24 जुलाई को ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री माननीय सर कीर स्टारर ने बकिंघमशायर स्थित यूके के प्रधानमंत्री के कंट्री रेजिडेंस 'चेकर्स' पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे आर्थिक साझेदारी और अवसरों का एक नया युग शुरू हुआ। इस समझौते ने ब्रिटेन में भारत के 99% निर्यात के लिए अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुंच सुनिश्चित की है, जो लगभग पूरे व्यापार क्षेत्र को कवर करता है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 56 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का संयुक्त लक्ष्य है। साथ ही, श्री मोदी और श्री स्टारर ने द्विपक्षीय संबंधों के सारे पहलुओं की समीक्षा की और भारत-यूके विजन 2035 को अपनाया

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री माननीय सर कीर स्टारर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अकेले बैठक के साथ-साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने ऐतिहासिक भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग और रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाएगा। दोनों पक्षों ने एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर बातचीत करने पर भी सहमति व्यक्त की, जो सीईटीए के साथ प्रभावी होगा और वाणिज्यिक इकाइयों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देकर और व्यापार करने की लागत को कम करके दोनों देशों के पेशेवरों और सेवा उद्योग को सुविधा प्रदान करेगा।

पूंजी बाजारों और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने रेखांकित किया कि दोनों पक्ष भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, गुजरात में गिफ्ट सिटी और यूके के जीवंत वित्तीय इकोसिस्टम के बीच अधिक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं।

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सारे पहलुओं की समीक्षा की और भारत-यूके विजन 2035 को अपनाया। विजन 2035 दस्तावेज़ अर्थव्यवस्था और विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान और शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई, स्वास्थ्य और एक दूसरे के बीच संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों में अगले दस वर्षों के लिए संबंधों को आगे बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अधिक महत्वाकांक्षा और नई गति का संचार करेगा।

रक्षा उत्पादों के सह-डिजाइन, सह-विकास और सह-उत्पादन में सहयोग

दोनों नेताओं ने दोनों देशों के साथ-साथ वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रक्षा उत्पादों के सह-डिजाइन, सह-विकास और सह-उत्पादन में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु रक्षा औद्योगिक रोडमैप को अंतिम रूप दिए जाने का भी स्वागत किया। दोनों देशों के सशस्त्र बलों की नियमित भागीदारी का स्वागत करते हुए उन्होंने गहरी होती रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर संतोष व्यक्त किया।

दोनों नेताओं ने नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पहल (टीएसआई) के तेज कार्यान्वयन का आह्वान किया, जो दूरसंचार, महत्वपूर्ण खनिज, एआई, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, उन्नत सामग्री और क्वांटम पर केंद्रित है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने शिक्षा क्षेत्र में भारत और यूके के बीच बढ़ती साझेदारी का भी स्वागत किया, जहां छह यूके के विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत भारत में परिसर खोलने के लिए काम कर रहे हैं। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय, जिसने 16 जून, 2025 को गुरुग्राम में अपना परिसर खोला, एनईपी के तहत भारत में अपना परिसर खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है।

श्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत के लोगों के प्रति प्रधानमंत्री श्री स्टारर के मजबूत समर्थन और एकजुटता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ

भारत-ब्रिटेन विजन 2035

भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने 24 जुलाई, 2025 को लंदन में द्विपक्षीय बैठक के दौरान नए 'भारत-ब्रिटेन विजन 2035' को साझा स्वीकृति प्रदान कर दी, जो पुनर्जीवित साझेदारी की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह महत्वाकांक्षी एवं भविष्य-केंद्रित समझौता, तेजी से बदलते वैश्विक दौर में आपसी विकास, समृद्धि और एक समृद्ध, सुरक्षित व सतत विश्व को आकार देने के लिए दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने के संकल्प को रेखांकित करता है।

विस्तारित महत्वाकांक्षा: भारत और ब्रिटेन ने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने के बाद से सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदारियों तथा विकास को गति दी है। नया दृष्टिकोण इसी सहभागिता को आगे बढ़ाता है और द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देने तथा विविधतापूर्ण बनाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है।

रणनीतिक दृष्टिकोण: भारत-ब्रिटेन के बीच प्रमुख साझेदारियां वर्ष 2035 तक दोनों देशों के संबंधों को पुनर्परिभाषित करेंगी और दोनों पक्षों के लिए परिवर्तनकारी अवसर तथा विशेष लाभ प्रदान करेंगी। भारत-ब्रिटेन विजन 2035 स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य लेकर चलेगा और यह मील के पत्थर स्थापित करता है, जिससे भविष्य में निरंतर सहयोग व नवाचार के लिए मार्ग प्रशस्त होता है।

व्यापक परिणाम: भारत-ब्रिटेन विजन 2035 के स्तंभों को एक-दूसरे को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे एक ऐसी संयुक्त साझेदारी का निर्माण होगा जो परिणामों की एक विस्तृत और गहन श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी के योग से भी अधिक बड़ी होगी, इसमें शामिल हैं:

- ब्रिटेन और भारत में विकास तथा नौकरियां एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते पर आधारित हैं, जो दोनों देशों के लिए बाजार व अवसरों को खोलेगा।
- वैश्विक प्रतिभा की अगली पीढ़ी को पोषित करने के लिए शिक्षा और कौशल साझेदारी, ब्रिटेन तथा भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सहयोग को आगे ले जाना, जिसमें एक-दूसरे के देशों में अग्रणी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना भी शामिल है।
- प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल पर आधारित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान का विकास करना, जो भविष्य के दूरसंचार, एआई व महत्वपूर्ण खनिजों पर केंद्रित हो और अर्धचालक, क्वांटम, जैव-प्रौद्योगिकी तथा उन्नत सामग्रियों पर भविष्य के सहयोग के लिए आधार तैयार करे।
- एक परिवर्तनकारी जलवायु साझेदारी, स्वच्छ ऊर्जा में तेजी लाने, बड़े पैमाने पर जलवायु वित्त जुटाने और लचीलेपन को बढ़ने पर केंद्रित है।
- रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, जिसमें हिंद-प्रशांत और उसके बाहर शांति, सुरक्षा व समृद्धि के लिए साझा प्रतिबद्धता शामिल है।

वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।

यात्रा के दौरान दोनों पक्षों द्वारा निम्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर/अपनाया गया:

- व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)
- भारत-यूके विजन 2035
- रक्षा औद्योगिक रोडमैप
- प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पहल पर वक्तव्य
- केंद्रीय जांच ब्यूरो, भारत और यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के बीच एमओयू

व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हुए हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 24 जुलाई को व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर करके भारत और ब्रिटेन ने एक मज़बूत आर्थिक साझेदारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। इस समझौते पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और व्यापार एवं व्यापार राज्य मंत्री श्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

यह मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और आर्थिक एकीकरण को मज़बूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दुनिया की क्रमशः चौथी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंध वैश्विक आर्थिक महत्व रखते हैं। भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर 6 मई, 2025 को घोषित वार्ता के सफल समापन के बाद हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 56 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का संयुक्त लक्ष्य है।

सीईटीए ने ब्रिटेन को भारत के 99% निर्यात के लिए अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुंच सुनिश्चित की है, जो लगभग पूरे व्यापार क्षेत्र को कवर करता है। इससे कपड़ा, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, खिलौने और रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों के साथ-साथ इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट और जैविक रसायन जैसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के एक मज़बूत चालक 'सेवा क्षेत्र' को भी व्यापक लाभ प्राप्त होंगे। यह समझौता आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय और कानूनी सेवाओं, पेशेवर और शैक्षिक सेवाओं और डिजिटल व्यापार में बेहतर बाज़ार पहुंच प्रदान करता है। भारतीय पेशेवर, जिनमें ब्रिटेन में सभी सेवा क्षेत्रों में काम करने के लिए कंपनियों द्वारा तैनात पेशेवर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, शेफ, योग प्रशिक्षक और संगीतकार जैसे अनुबंध पर तैनात पेशेवर शामिल हैं, सरल वीज़ा प्रक्रियाओं और उदार प्रवेश श्रेणियों से लाभान्वित होंगे, जिससे प्रतिभाओं के लिए ब्रिटेन में काम करना आसान हो जाएगा। ■

प्रधानमंत्री की मालदीव गणराज्य की यात्रा

'पड़ोसी प्रथम' नीति के अनुरूप मालदीव के साथ और अधिक मजबूत हुए संबंध

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25-26 जुलाई के दौरान मालदीव गणराज्य की दो दिवसीय सफल राजकीय यात्रा की। मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने प्रधानमंत्री का रिपब्लिक स्क्वायर पर औपचारिक स्वागत किया। श्री मोदी ने अपनी 'पड़ोसी प्रथम' और विजन महासागर नीतियों के अनुरूप मालदीव के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 25 जुलाई को माले स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की। यह बैठक सौहार्दपूर्ण रही और इससे दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता की पुष्टि हुई। प्रधानमंत्री ने उन्हें और उनके प्रतिनिधिमंडल को दिए गए शानदार आतिथ्य के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया और मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दीं। साथ ही दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के विशेष अवसर पर भी अपनी शुभकामनाएं दीं।

दोनों नेताओं ने सदियों से स्थापित मित्रता और विश्वास के गहरे बंधनों पर प्रकाश डाला, जो दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों से और मजबूत हुए हैं। दोनों नेताओं ने अक्टूबर, 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान अपनाए गए 'व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी' के लिए भारत-मालदीव साझा दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में प्रगति की भी समीक्षा की।

राष्ट्रपति श्री मुइज्जू ने मालदीव के समक्ष किसी भी संकट के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने की भारत की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने विकास साझेदारी, बुनियादी ढांचे के समर्थन, क्षमता निर्माण, जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया तथा इस संबंध में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तहत दोनों देशों के बीच सहयोग का उल्लेख किया।

आर्थिक साझेदारी की समीक्षा

दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की भी समीक्षा की।

प्रधानमंत्री ने मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में की सहभागिता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी माले यात्रा के दौरान 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में 'मुख्य अतिथि' के रूप में भाग लिया। यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की। प्रधानमंत्री श्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू द्वारा आमंत्रित किए जाने वाले राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष स्तर के पहले विदेशी नेता भी हैं।

प्रधानमंत्री ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ रिपब्लिक स्क्वायर में स्वतंत्रता दिवस परेड देखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने मालदीव की जनता और सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। समारोह में मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बलों और अन्य स्थानीय इकाइयों द्वारा एक जीवंत परेड का आयोजन किया गया, साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गईं, जिनमें एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में मालदीव की उपलब्धियों को दर्शाया गया।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और मालदीव की जनता को उनके सादर आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में 'मुख्य अतिथि' के रूप में उनकी भागीदारी भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर है। वर्ष 2025 में भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल भी पूरे होंगे।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता और द्विपक्षीय निवेश संधि दोनों पक्षों के लिए नये अवसर खोलेगी। इस बात पर गौर करते हुए कि दोनों देशों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना चाहिए, विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने यूपीआई को अपनाने, रुपे कार्ड की स्वीकृति और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार पर हाल की सहमति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ विकास साझेदारी पहले से ही मजबूत लोगों के बीच संबंधों को और अधिक मूल्यवान बना रही है।

दोनों नेताओं ने कहा कि ग्लोबल साउथ साझेदार के रूप में वे पृथ्वी और यहां के लोगों के लाभ के लिए जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, प्राकृतिक आपदा जोखिम में कमी लाने तथा जलवायु विज्ञान जैसे मुद्दों पर काम करना जारी रखेंगे।

श्री मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए राष्ट्रपति श्री मुइज्जू को धन्यवाद दिया।

दोनों नेताओं के बीच मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यूपीआई, भारतीय फार्माकोपिया और रियायती ऋण सुविधाओं के क्षेत्रों में छह समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान हुआ। नई ऋण व्यवस्था मालदीव में अवसंरचना विकास और अन्य गतिविधियों के लिए 4850 करोड़ रुपये (लगभग 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर) प्रदान करती है। मौजूदा ऋणों के लिए एक संशोधन समझौते का भी आदान-प्रदान किया गया। इससे मालदीव के वार्षिक ऋण सेवा दायित्वों में 40 प्रतिशत (51 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटाकर 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की कमी आएगी। दोनों पक्षों ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ की शर्तों का भी आदान-प्रदान किया।

प्रधानमंत्री ने 3,300 सामाजिक आवास इकाइयां और 72 वाहन भेंट किए

दोनों नेताओं ने अड्डू शहर में सड़क और जल निकासी प्रणाली परियोजनाओं और अन्य शहरों में 6 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल और आव्रजन अधिकारियों के लिए 3,300 सामाजिक आवास इकाइयां और 72 वाहन भेंट किए।

श्री मोदी ने मालदीव सरकार को आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब (भीष्म) की दो इकाइयां भी सौंपीं। अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के साथ इस क्यूब से 200 घायलों को चिकित्सा सहायता मिल सकती है और इसमें छह चिकित्साकर्मियों के दल को 72 घंटे तक सहायता प्रदान करने की क्षमता भी है।

प्रकृति संरक्षण के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता के अनुरूप दोनों नेताओं ने भारत के 'एक पेड़ मां के नाम' और मालदीव के '5 मिलियन वृक्षारोपण की प्रतिज्ञा' अभियान के तहत आम के पौधे लगाए।

श्री मोदी ने मालदीव और वहां के लोगों को उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार समर्थन देने तथा हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, विकास और समृद्धि के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

समझौता ज्ञापनों/समझौतों का आदान-प्रदान

- मालदीव को 4,850 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के लिए समझौता
- भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित ऋण सहायता पर मालदीव के वार्षिक ऋण चुकौती दायित्वों को कम करने पर संशोधन समझौता
- भारत-मालदीव मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के विचारार्थ विषय
- मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और मालदीव मौसम विज्ञान सेवा (एमएमएस), पर्यटन और पर्यावरण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन
- भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मालदीव के गृह सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- मालदीव द्वारा भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) को मान्यता देने पर समझौता ज्ञापन
- मालदीव में यूपीआई के उपयोग पर भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड (एनआईपीएल) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) के बीच नेटवर्क-टू-नेटवर्क समझौता

मालदीव के रक्षा मंत्रालय भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने 25 जुलाई को माले में मालदीव के अत्याधुनिक रक्षा मंत्रालय भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

हिंद महासागर के दृश्य के साथ ग्यारह मंजिला यह इमारत दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग का प्रतीक है। रक्षा मंत्रालय का भवन भारत की वित्तीय सहायता से निर्मित किया गया है और यह मालदीव के रक्षा एवं कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाने में योगदान देगा।

भारत-मालदीव राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने 25 जुलाई को भारत-मालदीव राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किए। उल्लेखनीय है कि मालदीव की 1965 में स्वतंत्रता के बाद भारत उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। स्मारक डाक टिकट जारी करना दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। ■

राज्य में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ-साथ 81 हजार से ज्यादा रोजगार का सृजन हुआः अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउंडिंग के अवसर पर 19 जुलाई को आयोजित 'उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025' समारोह और प्रदेश सरकार की 1271 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी भूषण, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा और योगगुरु बाबा रामदेव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

'उत्तराखंड निवेश उत्सव' को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि वह उत्तराखंड आने पर हर बार एक नई ऊर्जा लेकर लौटते हैं। उत्तराखंड में आते ही चारों धामों में बैठे देवी-देवताओं, गंगा-यमुना और यहां आध्यात्म की अलख जगाने वाले संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2023 में उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इंवेस्टर समिट में जब मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बताया कि राज्य में 3 लाख 56 हजार करोड़ रुपए के एमओयू आए हैं, तो उन्होंने श्री धामी से कहा था कि एमओयू लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें जमीन पर उतारना बड़ा काम है। श्री शाह ने कहा कि आज उत्तराखंड में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जमीनी सच्चाई बन चुका है।

उन्होंने कहा कि राज्य में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ-साथ 81 हजार से ज्यादा रोजगार का सृजन हुआ है, इनके सहायक उद्योग से (ancillary industry) से ढाई लाख नए रोजगार पैदा होने की संभावना है और सबसे बड़ी बात है कि टायर-टू और टायर-थ्री शहरों तक निवेश पहुंचा है।

10 साल में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 60 प्रतिशत की वृद्धि

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 10 साल में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 60 प्रतिशत की वृद्धि की है। ग्रामीण क्षेत्रों में नई आठ लाख किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया है। देश के 333 जिलों में सुविधाजनक 'वंदे भारत' ट्रेन पहुंची है। 45 हजार किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ है। 88 नए हवाई अड्डे बने और इनलैंड वाटर वे कार्गो में 11 गुणा वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलों अनाज मुफ्त देकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा देने से अस्पताल में भर्ती होने पर आने वाला उनका खर्च माफ हो गया, 16 करोड़ घरों में आजादी के बाद पहली बार नल आया, 12 करोड़ घरों में शौचालय बने, 13 करोड़ घरों में एलपीजी सिलिंडर पहुंचा, 3 करोड़ घरों में पहली बार बिजली आई और चार करोड़ लोगों को घर दिए। इसके साथ ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम भी किया गया।

मुख्य बातें

- मोदी जी छोटे व पूर्वी राज्यों के विकास से देश का एक समान विकास कर रहे हैं
- एक लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई
- आयुर्वेद, योग, ऑर्गेनिक खेती व प्राकृतिक उपचार उत्तराखंड के विकास के चार प्रमुख आधार बनने वाले हैं
- विपक्ष राज्यों के विकास के हवन में हड्डी डालना बंद करे
- मोदी जी ने यह मिथक तोड़ दिया है कि औद्योगिक विकास और गरीब कल्याण एक साथ नहीं हो सकते
- जहां एक ज्योतिर्लिंग, तीन शक्तिपीठ, चार धाम, पंच प्रयाग, पंच केदार और सप्त बद्री जैसे पवित्र स्थल विराजमान हों, उस उत्तराखंड के विकास को कोई नहीं रोक सकता ■

विकसित भारत की ओर एक और बड़ा कदम ब्रिटेन के साथ ट्रेड से अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

पीयूष गोयल के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक पहचान मिलेगी। यह समझौता मोदी सरकार की 2047 तक भारत को विकसित बनाने की रणनीति का हिस्सा है। समझौते से कृषि निर्यात में वृद्धि होगी किसानों को लाभ होगा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए अवसर उत्पन्न होंगे

पीयूष गोयल

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर सहमति बन गई है। भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) के अस्तित्व में आने से रोजगार के असंख्य अवसर सृजित होंगे। भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और व्यवसायों को नई वैश्विक पहचान मिलेगी। उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की किफायती दरों पर पहुंच भी सुनिश्चित होगी।

सीईटीए की संकल्पना आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के अनुरूप ही है। यह मोदी सरकार की भारत को 2047 तक विकसित बनाने की संकल्पना से जुड़ी रणनीति का एक हिस्सा है।

मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास को फिर से स्थापित करने तथा इसे भारतीय और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक दृढ़ रणनीति अपनाई है। विकसित देशों के साथ एफटीए इस रणनीति के केंद्र में है। ऐसे समझौते व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं।

पिछली यूपीए सरकार ने भारत के दरवाजे प्रतिद्वंद्वी देशों के लिए खोलकर भारतीय व्यवसायों को खतरे में डालने वाला रवैया अपनाया था। यूपीए सरकार में विकसित देश भारत के साथ व्यापार समझौते के अनिच्छुक थे, क्योंकि तब देश की गिनती दुनिया की पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी थी। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिकी की काया ही पलट गई।

ब्रिटेन के साथ यह व्यापार समझौता बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाएगा। यह करीब 99 प्रतिशत टैरिफ समाप्त करता है, जो लगभग शत प्रतिशत व्यापार मूल्य को कवर करता है। यह 56 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के लिए अपार अवसर बनाएगा, जिसके 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है। इससे छोटे व्यवसाय समृद्ध होंगे, क्योंकि भारतीय उत्पादों को प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी

भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2014 से लगभग तिगुना बढ़कर लगभग 331 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

क्रांतिकारी सुधारों, कारोबारी सुगमता और प्रधानमंत्री के वैश्विक व्यक्तित्व ने भारत को एक आकर्षक आर्थिक गंतव्य के रूप में उभारने में मदद की है, जहां विपुल संभावनाएं हैं। आज दुनिया भारत की अद्भुत विकासगाथा का हिस्सा बनना चाहती है। प्रमुख देशों द्वारा एक के बाद एक एफटीए इसी मान्यता की पुष्टि करते हैं।

ब्रिटेन के साथ यह व्यापार समझौता बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाएगा। यह करीब 99 प्रतिशत टैरिफ समाप्त करता है, जो लगभग शत प्रतिशत व्यापार मूल्य को कवर करता है। यह 56 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के लिए अपार अवसर बनाएगा, जिसके 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है। इससे छोटे व्यवसाय समृद्ध होंगे, क्योंकि भारतीय उत्पादों को प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी।

खेल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के कारोबार में भारी विस्तार होगा। विश्व के एक आकर्षक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त चमड़ा और जूते, वस्त्र, समुद्री उत्पाद और रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए मददगार साबित होगी।

इन क्षेत्रों में, जहां कई छोटे व्यवसाय संचालित होते हैं, निवेश और रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। भारत के चमड़ा और जूता निर्यात में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत वस्त्र, चमड़ा और जूते के क्षेत्र में ब्रिटेन के शीर्ष तीन आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनने की बेहतर स्थिति में है।

इस समझौते के बाद 95 प्रतिशत से अधिक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क लगेगा, जिससे कृषि निर्यात और ग्रामीण समृद्धि में तेज वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे अगले तीन वर्षों में

घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए एफटीए में भारत के सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। भारत ने डेरी उत्पादों, सेब, जई और खाद्य तेलों पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी है। यह मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और कमजोर कृषक समुदायों को प्राथमिकता देने की रणनीति को दर्शाता है

कृषि निर्यात में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का अनुमान है, जो 2030 तक भारत के 100 अरब डालर के कृषि-निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देगा।

इससे भारतीय किसानों के लिए प्रीमियम ब्रिटिश बाजार के द्वार खुलेंगे, जो जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ के देशों को मिलने वाले फायदे के बराबर या उससे भी अधिक होगा। हल्दी, काली मिर्च, इलायची, प्रसंस्कृत उत्पादों, अचार और दालों को भी शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। निर्यात बढ़ने से कृषि आय में वृद्धि होगी तथा गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रमाणन के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इससे कृषि मूल्य श्रृंखला में रोजगार के असंख्य अवसर सृजित होंगे।

घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए एफटीए में भारत के सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। भारत ने डेरी उत्पादों, सेब, जई और खाद्य तेलों पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी है। यह मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और कमजोर कृषक समुदायों को प्राथमिकता देने की रणनीति को दर्शाता है।

समझौते से भारतीय मछुआरों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु के मछुआरों की ब्रिटिश बाजार में पहुंच सुगम होगी। यह समझौता सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबंधित सेवाओं, वित्तीय सेवा और शिक्षा सहित अन्य सेवाओं में भारतीयों के लिए नए अवसर बनाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के एफटीए वस्तुओं और सेवाओं से कहीं आगे तक जाते हैं। आस्ट्रेलियाई एफटीए के साथ भारत ने दोहरे कराधान का मुद्दा सुलझाया, जो आईटी कंपनियों की परेशानी बढ़ा रहा था। ब्रिटेन के साथ समझौते का एक अहम बिंदु दोहरे अंशदान से जुड़ा है। यह ब्रिटेन में नियोक्ताओं, अस्थायी भारतीय कर्मियों को तीन वर्षों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

व्यापार समझौते प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च-गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त करने में मदद मिलती है। मोदी सरकार ने गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन प्रदान किया है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं और मुक्त व्यापार समझौतों पर बात आगे बढ़ाई है।

सरकार ने किसी भी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर से पहले उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श किया है। यह जानकर खुशी होती है कि उद्योग जगत ने इन व्यापार समझौतों का व्यापक रूप से समर्थन एवं स्वागत किया है। इसी कड़ी में ब्रिटेन के साथ यह समझौता बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों के लिए एक मानक है।

यह हमारे मूल हितों से समझौता किए बिना, वंचित समुदायों के लिए आकर्षक वैश्विक अवसरों के द्वार खोलता है। यह इस बात का एक प्रखर उदाहरण भी है कि नया भारत व्यापार किस प्रकार करता है।

(लेखक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं)

समुद्री विकास को बढ़ावा देते हुए विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हुआ

सर्बानंद सोनोवाल

भारत के बंदरगाह लाजिस्टिक नोड्स की पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर वाणिज्य के आधुनिक प्रवेश द्वार बन रहे हैं। क्षमता विस्तार, मशीनीकरण, डिजिटलीकरण और व्यापार सुगमता पर ध्यान केंद्रित करने से विशाखापत्तनम, मुंद्रा, जेएनपीए और कामराजर जैसे बंदरगाह वैश्विक रैंकिंग में ऊपर पहुंच गए हैं।

विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) 2023 ने भारत की दक्षता को मान्यता देते हुए इसे कई विकसित देशों से आगे रखा है। देश ने प्रमुख लॉजिस्टिक्स संकेतकों में सुधार किया है और 2023 में 139 देशों में हम 38वें स्थान पर है, जबकि 2014 में भारत 54वें स्थान पर था। इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंकिंग में भी काफी सुधार हुआ है और हम 44वें से 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि औसत कंटेनर ठहराव समय घटकर लगभग 2.6 दिन रह गया है, जो वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी आंकड़ा है। प्रमुख बंदरगाहों का टर्नअराउंड समय (टीआरटी) भी लगभग 94 घंटों से घटकर लगभग 48.06 घंटे रह गया है।

इस प्रगति का आधार पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास है। पिछले एक दशक में हमारे प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 800.5 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 1,681 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) हो गई है। अब तक कुल 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 98 बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे बंदरगाहों की वार्षिक क्षमता में 230 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक की वृद्धि हुई है।

प्रमुख बंदरगाहों का वित्तीय प्रदर्शन भी उतना ही प्रभावशाली रहा है, कुल आय वित्त वर्ष 2015 के 11,760 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 24,203 करोड़ रुपये हो गई— जो 10 वर्षों में 7.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) है। इसी अवधि में 13 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से परिचालन अधिशेष लगभग तीन गुना बढ़कर 12,314 करोड़ रुपये हो गया। परिचालन दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, परिचालन अनुपात वित्त वर्ष 2015 के 64.7 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 42.3 प्रतिशत हो गया, जिससे बंदरगाहों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है।

विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) 2023 ने भारत की दक्षता को मान्यता देते हुए इसे कई विकसित देशों से आगे रखा है। देश ने प्रमुख लॉजिस्टिक्स संकेतकों में सुधार किया है और 2023 में 139 देशों में हम 38वें स्थान पर है, जबकि 2014 में भारत 54वें स्थान पर था। इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंकिंग में भी काफी सुधार हुआ है और हम 44वें से 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि औसत कंटेनर ठहराव समय घटकर लगभग 2.6 दिन रह गया है, जो वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी आंकड़ा है। प्रमुख बंदरगाहों का टर्नअराउंड समय (टीआरटी) भी लगभग 94 घंटों से घटकर लगभग 48.06 घंटे रह गया है

तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल (टीआईसीटी) जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं और 76,000 करोड़ रुपये के वधावन बंदरगाह का शिलान्यास, बुनियादी ढांचे और रसद दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। हमारा विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह भारत की ट्रांस-शिपमेंट क्षमताओं को बढ़ावा देगा।

विश्व बैंक की सीपीपीआई 2023 रिपोर्ट में दस भारतीय बंदरगाह अब ग्लोबल टॉप 100 में जगह बना चुके हैं, विशाखापत्तनम पोर्ट 2022 में 122वें स्थान से बढ़कर 19वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत आधुनिक लॉजिस्टिक्स के लिए अपनी नदियों की क्षमता, जो कभी वाणिज्य की जीवंत धमनियां थीं, पुनः प्राप्त कर रहा है। एनडीए सरकार के तहत गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित 106 नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में उन्नत किया गया है। इससे अंतर्देशीय जलमार्ग आधारित माल ढुलाई में सात गुना वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2014 में 18.1 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से वित्त वर्ष 2025 में 146 एमएमटी हो गई है। यह क्षेत्र अब मल्टीमॉडल टर्मिनलों, रात्रि नेविगेशन और डिजिटल निगरानी प्रणालियों से सुसज्जित है। इस पुनरुद्धार की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित हुआ है, जिनके सहयोग से प्रौद्योगिकी में वृद्धि हुई है तथा टिकाऊ माल ढुलाई को बढ़ावा मिला

है। वित्त वर्ष 2026 के लिए 1,700 करोड़ रुपये का व्यय का लक्ष्य रखा गया है, जो 1986 से 2014 तक यानी 28 वर्षों के दौरान अंतर्देशीय जलमार्गों पर किये गये कुल व्यय से अधिक है।

अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग के लिए 35 प्रतिशत प्रोत्साहन प्रदान करने वाली कार्गो प्रमोशन योजना इस वृद्धि को और बढ़ावा देती है। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद् (आईडब्ल्यूडीसी) की पहली बैठक में 2047 तक नदी-परिभ्रमण पर्यटन विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

क्रूज़ पर्यटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अब मुंबई, कोच्चि, गोवा और विशाखापत्तनम जैसे भारतीय बंदरगाहों पर डॉक कर रही हैं। सितंबर, 2024 में 'क्रूज़ भारत मिशन' की शुरुआत की गयी, जिसका लक्ष्य 2029 तक क्रूज़ यात्रियों की संख्या को दोगुना करना है, जिसमें छह नए अंतरराष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनलों को स्थापित करने की योजना है। समुद्री क्रूज़ यात्रियों की संख्या 2014 के 84,000 से बढ़कर 2024-25 में 4.92 लाख हो गई, जो 500 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्शाता है।

समुद्री क्षेत्र में स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अग्रणी हरित पहलों के माध्यम से स्पष्ट है। हरित सागर हरित बंदरगाह दिशानिर्देशों का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, और ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) का लक्ष्य 2030 तक प्रमुख बंदरगाहों के जहाजों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 30 प्रतिशत की कमी लाना है, जो कि समुद्री अमृत काल विज़न 2047 के अनुरूप है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत तीन प्रमुख बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन या अमोनिया हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। हरित नौका दिशानिर्देश 2047 तक 100 प्रतिशत हरित जहाजों को बढ़ावा देते हैं और भारत ने अपना पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत भी लॉन्च किया है।

भारत को 2024-25 की द्विवार्षिक अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) की परिषद् में सर्वोच्च मतों के साथ पुनः निर्वाचित किया गया है। सहयोग के नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, विशेष रूप से भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ अंतर-सरकारी ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर ने इसे नई गति दी है। ईरान के साथ शाहिद बेहेश्टी बंदरगाह टर्मिनल, चाबहार के विकास के लिए हस्ताक्षरित दीर्घकालिक अनुबंध, मध्य एशिया के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) को खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बुनियादी ढांचे के अलावा, मानव पूंजी और विरासत भी प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। पिछले दशक में वैश्विक समुद्री समुदाय में भारत की उपस्थिति में 200 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, जिससे सक्रिय भारतीय नाविकों की संख्या 2014 में 1.08 लाख से बढ़कर इस वर्ष 3.20 लाख हो गई है। महिला नाविकों की संख्या 2014 में 341 से बढ़कर 2025 में 2,557 हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान योजना भी शुरू की है।

क्रूज़ पर्यटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अब मुंबई, कोच्चि, गोवा और विशाखापत्तनम जैसे भारतीय बंदरगाहों पर डॉक कर रही हैं। सितंबर, 2024 में 'क्रूज़ भारत मिशन' की शुरुआत की गयी, जिसका लक्ष्य 2029 तक क्रूज़ यात्रियों की संख्या को दोगुना करना है, जिसमें छह नए अंतरराष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनलों को स्थापित करने की योजना है। समुद्री क्रूज़ यात्रियों की संख्या 2014 के 84,000 से बढ़कर 2024-25 में 4.92 लाख हो गई, जो 500 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्शाता है

गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विश्व स्तरीय समुद्री संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करना और साथ ही प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन का आयोजन, भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

वित्त वर्ष 2026 के बजट में जहाज निर्माण और जहाज पुनर्चक्रण के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की एक श्रृंखला की घोषणा की गई, जिसमें समुद्री विकास निधि, जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति 2.0, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर सूची में निर्दिष्ट आकार से बड़े बड़े जहाजों को शामिल करना, जहाज निर्माण समूहों को सुविधाजनक बनाने के उपाय, अंतर्देशीय जहाजों के लिए टन भार कर व्यवस्था का विस्तार, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत के लिए कच्चे माल और घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क छूट का अगले 10 वर्षों के लिए विस्तार शामिल है।

इन पहलों ने प्रमुख वैश्विक जहाज निर्माण कंपनियों को भारतीय शिपिंग कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए आकर्षित करना शुरू कर दिया है। इससे रोजगार के व्यापक अवसर और निवेश में वृद्धि होना निश्चित है।

संक्षेप में, पिछले दशक ने भारत की समुद्री यात्रा में एक निर्णायक बदलाव का संकेत दिया है। भारत तेज़ी से व्यापार, नवाचार और निवेश के लिए एक पसंदीदा समुद्री गंतव्य के रूप में उभर रहा है, क्योंकि यह विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

(लेखक केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं)

देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक
कारगिल की वीरगाथा

तरुण चुग

मैं जब भी द्रास जाता हूं और टाइगर हिल की ऊंचाइयों को देखता हूं, तो ऐसा लगता है मानो समय वहीं ठहर गया हो, जहां हमारे जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों पर मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं वहां कई बार गया हूं, और हर बार जब उस धरती पर कदम रखता हूं, एक गहरी अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति जो न तो शब्दों में बंधती है, न ही भूलती है।

कारगिल का वह भयावह दृश्य आज भी स्मृतियों में जीवंत हो उठता है। दुर्गम, नुकीली, घने कोहरे में लिपटी सीधी खड़ी पहाड़ियां — जिन पर दुश्मन की ओर से आग उगलती तोपों और बरसती गोलियों की बौछार के बीच हमारे वीर जवानों ने अदम्य साहस के साथ चढ़ाई की। देश की अस्मिता, भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। जब भी इस विषय पर लेखनी उठाता हूं, मन मानो उन्हीं वीरभूमियों में विचरने लगता है। मुझे प्रतीत होता है कि मैं स्वयं उन चट्टानों, उन घाटियों और उन कठिन रास्तों से होकर गुजर रहा हूं जहां हमारे जवानों ने अपना रक्त बहाया। कारगिल की हर एक चोटी, हर एक पत्थर, हर एक कंकर, मानो शौर्य का प्रतीक बनकर खड़ा है। वहां की हवाओं में आज भी हमारे जवानों के बलिदान की गूंज है, जो भारत माता की महानता का गान करती हैं।

वहां के स्मारक पर अंकित 559 नाम सिर्फ शहीदों की सूची नहीं हैं, वो भारत मां के वीर सपूतों की अमर गाथाएं हैं। टाइगर हिल को देखते हुए मन में यह भाव आता है कि हमारे सैनिकों ने किन असंभव हालात में लड़ाई लड़ी, चोटियों पर चढ़ाई की और तिरंगा फहराया। वहां की हवा में एक अनकहा गुरुत्व है, जो चेतना को झकझोरता है, जो हर भारतीय को याद दिलाता है कि राष्ट्र की रक्षा केवल शब्दों से नहीं होती, बल्कि बलिदान की आखिरी सीमा तक जाने से होती है।

कारगिल विजय दिवस पर भारत 1999 के कारगिल युद्ध में हमारी सेनाओं की विजय का स्मरण करता है, यह दिन हमारे राष्ट्रीय इतिहास में गर्व से अंकित है। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नई दिल्ली स्थित अमर जवान ज्योति जैसे स्मारकों पर कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि का नेतृत्व करते हैं। इस विजय के आज 26 वर्ष पूरे होने पर यह दिवस हमारे सैनिकों की वीरता और बलिदान की याद दिलाता है तथा प्रत्येक भारतीय के हृदय में एकता, गर्व और कृतज्ञता का संचार करता है।

कारगिल युद्ध असाधारण वीरता का एक अद्वितीय अध्याय था। पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा चोरी-छिपे भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के बाद भारतीय सेना ने मई 1999 में उन घुसपैठियों को कारगिल की बर्फीली चोटियों से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। दो महीनों से अधिक समय तक हमारे जवानों ने 16,000-18,000 फुट की ऊंचाई पर जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पहाड़ी परिस्थितियों में भीषण लड़ाइयां लड़ीं। भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर के तहत बर्फ से ढके पहाड़ों पर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के 559 सैनिकों और अधिकारियों ने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारे जवानों के साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर सेना ने तोलोलिंग और टाइगर हिल जैसी महत्वपूर्ण चोटियों को दुश्मन के कब्जे से फिर मुक्त कराया। सचमुच, हमें अपने कई सपूत खोने पड़े, लेकिन दुश्मन को अपनी पवित्र भूमि का एक इंच टुकड़ा भी नहीं लेने दिया। राष्ट्र इन वीरों का सदैव ऋणी रहेगा, जिनकी असाधारण वीरता ने कठिनतम परिस्थितियों में भी हमारी संप्रभुता की रक्षा की।

कारगिल युद्ध से कुछ ही माह पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए थे और वहां पाकिस्तान से स्थायी शांति की उम्मीद में दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन धोखेबाज पाकिस्तान ने इस सद्भावना का जवाब विश्वासघात से दिया – गुपचुप अपनी सेना को कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमाने भेज दिया, जिससे दोनों देशों के बीच हुए लाहौर समझौते का खुला उल्लंघन हुआ। वाजपेयी जी ने क्षोभ प्रकट करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने "लाहौर में समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कारगिल में घुसपैठ करके भारत के साथ विश्वासघात किया।" फिर भी, पाकिस्तान की इस चाल का भारत ने तुरंत और दृढ़ उत्तर दिया। वाजपेयी जी ने हमारी सशस्त्र सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब की पूरी छूट दी और साथ ही भारत के पक्ष में वैश्विक समर्थन जुटाया, एवं कारगिल युद्ध में भारत विजयी हुआ।

इस युद्ध ने पूरे भारत को अभूतपूर्व एकता के सूत्र में बांध दिया। पहाड़ों पर हमारे जवान बहादुरी से लड़ रहे थे और इधर देशभर के लोग उनके समर्थन में एकजुट हो गए। देशभक्ति की लहर सी आ गई – नागरिकों ने प्रार्थना सभाएं कीं, स्कूली बच्चों ने मोर्चे पर डटे सैनिकों को पत्र भेजे, और हजारों लोगों ने घायलों के लिए स्वेच्छा से रक्तदान किया। कारगिल के शहीदों के नाम हर जुबान पर थे; कई समुदायों ने उन वीरों के सम्मान में सड़कों, छात्रवृत्तियों और खेल प्रतियोगिताओं के नाम उनके नाम पर रखे। मोर्चे पर दिखा जवानों का साहस और जनता का अटूट संकल्प एक-दूसरे के पूरक थे। इससे स्पष्ट संदेश गया कि भारत की जनता अपनी सशस्त्र सेनाओं के साथ चट्टान की तरह खड़ी है।

राजनीतिक दृष्टि से भी कारगिल विजय ने दिखा दिया कि मज़बूत और निर्णायक नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय

जनता पार्टी ने हमेशा भारत के राष्ट्रीय हितों की दृढ़ रक्षा को सर्वोपरि माना है – कारगिल युद्ध ने हमारी इस नीति को सही साबित किया। कुछ लोगों ने समय-समय पर नरम रुख अपनाने या अल्पकालिक शांति के लिए समझौता करने की बात कही, किंतु वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि आक्रमण का उत्तर दृढ़ प्रतिरोध से ही दिया जाएगा। देशहित के प्रति यही स्पष्टता और राष्ट्रवादी संकल्प – जो भाजपा के मूल सिद्धांतों में है – पाकिस्तान के विश्वासघात को भारत की जीत में बदलने में निर्णायक सिद्ध हुआ।

कारगिल की विरासत सिर्फ स्मरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने हमें एक नए संकल्प से भी भर दिया – एक मजबूत और सुरक्षित भारत के निर्माण का संकल्प। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने और हमारे सैनिकों का मान-सम्मान बढ़ाने को अपना लक्ष्य बना लिया है। दशकों से अटकी 'वन रैंक, वन पेंशन' जैसी योजना को आखिरकार लागू किया गया, जिससे पूर्व सैनिकों को न्याय मिला। सेनाओं में ऐतिहासिक सुधार, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद, किए गए हैं, ताकि हमारी सुरक्षा संरचना अधिक प्रभावी और समन्वित हो। हमारी सेनाओं को आधुनिक शस्त्रों और तकनीकों से लैस किया जा रहा है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को इतना मजबूत बनाया गया है कि सेना किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब दे सके। उतना ही महत्वपूर्ण यह कि जवानों के प्रति सम्मान का एक नया संस्कार स्थापित किया गया है। अब हर दिवाली प्रधानमंत्री अग्रिम चौकियों पर जाकर जवानों के साथ त्योहार मनाते हैं, वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कारगिल में जवानों संग दिवाली मनाई, यह संदेश देते हुए कि राष्ट्र हर पल अपने इन प्रहरियों के साथ खड़ा है। एक ऐतिहासिक पहल के तहत अंडमान-निकोबार के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र विजेता वीरों, जिनमें कारगिल के नायक भी शामिल हैं, के नाम पर रखा गया है, ताकि उनकी वीरता सदा के लिए अमर हो और आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा मिलती रहे। पूरे देश में विजय दिवस आज गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है, द्रास के युद्ध स्मारक पर होने वाले समारोहों से लेकर युवाओं की पहलों तक। उदाहरण के लिए, जम्मू-कश्मीर में भाजपा के युवा मोर्चा की टीमें पूरे प्रदेश में 'विजय ज्योति' जलाकर ले जाती हैं, शहीदों को नमन करने के लिए और पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिए कि वह किसी नापाक हरकत की हिम्मत न करे। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 2025 के ऑपरेशन सिन्दूर तक, मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि भारत आतंकवाद या आक्रामकता के हर कृत्य का मुंहतोड़ जवाब देगा। चाहे नए स्मारकों का निर्माण हो, सैनिक कल्याण के उपाय हों या शत्रुओं के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई – कारगिल का जज़्बा देश के नेतृत्व को लगातार मार्गदर्शन देता आ रहा है कि भारत की सुरक्षा हर कीमत पर सुनिश्चित की जाए।

1999 में जब कारगिल युद्ध जारी था, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्वयं कारगिल पहुंचे थे, जहां उन्होंने युद्धक्षेत्र में डटे भारतीय जवानों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। यह वही सोच और जुड़ाव है जो आज भी जारी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वे हर साल दीपावली अग्रिम चौकियों पर देश के जवानों के साथ मनाते हैं, चाहे वह सियाचिन हो, कारगिल हो या अरुणाचल की बर्फीली सीमाएं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उस निरंतरता का प्रतीक है, जिसमें देश की रक्षा करने वालों के साथ सबसे पहले खड़ा होना उनकी प्राथमिकता है।

आज का भारत आतंकवाद को बर्दाश्त करने वाला भारत नहीं है। कारगिल के समय हमने अपनी ज़मीन पर कब्जा करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, और आज जब भी हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला होता है, भारतीय सेना उसी संकल्प के साथ जवाब देती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन 'सिन्दूर' इस नए भारत की सोच का प्रतीक है, जहां आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति है। यह ऑपरेशन उस क्षेत्र में चलाया गया जहां आतंकियों ने कायरतापूर्वक हमला किया था। सेना ने न केवल इलाके की घेराबंदी की, बल्कि एक-एक आतंकवादी को ढूंढकर समाप्त करने का संकल्प दिखाया। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अब न तो रक्षात्मक है, न मौन। आतंकवाद अब किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा, न सीमाओं पर, न सीमाओं के भीतर।

कारगिल युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारत की एकता, साहस और देशभक्ति की जीवंत मिसाल था। युद्ध के दौरान समूचे देश में देशभक्ति की भावना उमड़ पड़ी थी। हर नागरिक भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और वीर सैनिकों के बलिदान ने राष्ट्र को गर्व से भर दिया। धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर देशवासियों ने एकजुट होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्थन और श्रद्धा व्यक्त की। यह युद्ध न केवल सीमाओं पर लड़ा गया, बल्कि यह देश के हर नागरिक के दिल में लड़ा गया एक भावनात्मक संग्राम था।

कारगिल विजय दिवस हमारे लिए बतौर एक राष्ट्र अपनी एकता और संकल्प को पुनः दृढ़ करने का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की संप्रभुता और सम्मान पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और हमें सदैव सजग व तैयार रहना होगा। जब हम कारगिल के वीर नायकों को सलाम करते हैं, तो हमें यह भी प्रण लेना होगा कि उनके बलिदान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए हम सतर्क, देशभक्त और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। हमें भारत मां के उन रक्षकों का हाथ मजबूत करना है, फिर चाहे वे सीमा पर खड़े सैनिक हों या राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला नेतृत्व। कारगिल में मिली विजय भारत के अदम्य जज़्बे की विजय थी, जो किसी भी चुनौती के सामने नहीं झुकता। आज वही जज़्बा पहले से भी अधिक प्रखर है और हमें इसी भावना के बल पर एक ऐसा भारत गढ़ना है, जो न केवल मज़बूत और एकजुट हो, बल्कि सचमुच अजेय हो।

जय हिंद!

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

मातृभूमि की सच्ची सेवा के लिए समर्पित मोदी सरकार के अविस्मरणीय 11 वर्ष

राजकुमार चाहर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 11 वर्षीय कार्यकाल एक स्वर्णिम युग के रूप में याद किया जाएगा जिसने विकसित भारत और आत्मनिर्भर राष्ट्र की मजबूत आधारशिला रखी।" प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करने के साथ-साथ विश्व स्तर पर भारत की शक्ति को प्रदर्शित करते हुए परचम फहराया। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश को 'विश्वसनीयता का प्रतीक' बना दिया। स्वतंत्रता के बाद 65 वर्षों तक कांग्रेस और अस्थिर सरकारों के चलते आम नागरिक का विश्वास टूट गया था और भारत की वैश्विक छवि धूमिल हुई थी। लेकिन पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में एक भ्रष्टाचार-मुक्त, तुष्टीकरण-मुक्त और एकजुट भारत की स्थापना हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक कल्याण, सुशासन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। इस अवधि में भारत ने सामाजिक कल्याण, सुशासन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। मोदी सरकार की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही इसकी पहचान बन गई है। 'विकास और विरासत' के बीच नया संतुलन स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब लाभ इस आधार पर नहीं मिलता कि कोई कौन है, बल्कि निष्पक्षता के आधार पर मिलता है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास' आज सरकार की पहचान बन गया है। 2014 से पहले तक भारत की छवि थी कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अब यदि कोई हमारे ऊपर युद्ध थोपता है, आतंक फैलाता है या हमारी सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है, तो जवाब होगा– सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर। ये सब 'मेड इन इंडिया' के माध्यम से हुआ है और दुनिया ने भारत की शक्ति देखी है। 1952 से लागू अनुच्छेद 370 को हमारी सरकार ने समाप्त किया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की एकता को मजबूत किया। मोदी सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान' चलाकर महिलाओं को किया सशक्त।

2014 से पहले तक भारत की छवि थी कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अब यदि कोई हमारे ऊपर युद्ध थोपता है, आतंक फैलाता है या हमारी सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है, तो जवाब होगा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर। ये सब 'मेड इन इंडिया' के माध्यम से हुआ है और दुनिया ने भारत की शक्ति देखी है। 1952 से लागू अनुच्छेद 370 को हमारी सरकार ने समाप्त किया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की एकता को मजबूत किया। मोदी सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान' चलाकर महिलाओं को किया सशक्त

मोदी सरकार ने कृषि और किसान को प्राथमिकता देते हुए 11 वर्षों में विभिन्न सरकारी योजनाओं और बढ़े हुए बजटीय आवंटन के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र में 'व्यापक परिवर्तन' हुआ है, जिससे किसानों को खाद्य सुरक्षा से लेकर वैश्विक खाद्य नेतृत्व तक देश का नेतृत्व करने का अधिकार मिला। इस परिवर्तन ने छोटे किसानों, महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और संबद्ध क्षेत्रों का समर्थन करके समावेशिता पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि भारत को वैश्विक कृषि नेता के रूप में स्थापित किया है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया है, जो बीज से बाजार तक के दर्शन पर आधारित है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए बजट अनुमान 2013-14 में 27,663 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1,37,664.35 करोड़ रुपये हो गया है, जो लगभग पांच गुना वृद्धि है। भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2014-15 में 26.50 करोड़ टन से बढ़कर 2024-25 में अनुमानित 34.74 करोड़ टन हो गया है, जो कृषि उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्शाता है। मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। गेहूं का एमएसपी 2013-14 में 1,400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2024-25 में 2,425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, जबकि धान का मूल्य 2013-14 में 1,310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2025-26 में 2,369 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। फरवरी, 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना के तहत सरकार ने 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.7 लाख करोड़ रुपये वितरित किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने 7.71 करोड़ किसानों को लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का ऋण

प्रदान किया है। खरीद के आंकड़े विभिन्न फसलों में सुधार दर्शाते हैं। वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच खरीफ फसल की खरीद कुल 78.71 करोड़ टन रही, जबकि 2004-05 से 2013-14 के बीच यह खरीद 46.79 करोड़ टन थी। एमएसपी पर दलहनों की खरीद 2009-2014 के दौरान 1,52,000 टन से बढ़कर 2020-2025 के दौरान 83 लाख टन हो गई, जबकि एमएसपी पर तिलहन की खरीद पिछले 11 वर्षों में कई गुना बढ़ गई। सरकार का दृष्टिकोण आधुनिक सिंचाई, ऋण पहुंच, डिजिटल बाज़ार और कृषि-प्रौद्योगिकी नवाचारों पर केंद्रित रहा है, जबकि बाजरा की खेती और प्राकृतिक खेती जैसी पारंपरिक प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित किया गया है। डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों का भी विस्तार हो रहा है। जैसे-जैसे भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, इसके सशक्त किसान देश को खाद्य सुरक्षा से लेकर वैश्विक खाद्य नेतृत्व तक ले जाने के लिए तैयार हैं। मातृभूमि और भारत माता की सच्ची सेवा करते हुए मोदी जी ने इन 11 वर्षों में ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसके लिए हम मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करते हुए उनकी देशवासियों के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण को समर्पित यह वाक्य सार्थकता प्रदान करता हैं– 'जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। ■

(लेखक भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद हैं)

'सहकार एवं रोजगार उत्सव' जयपुर, राजस्थान

आज 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 17 जुलाई को राजस्थान के जयपुर में 'सहकार एवं रोजगार उत्सव' में राजस्थान के विभिन्न जिलों के 8 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा, केन्द्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

'सहकार एवं रोजगार उत्सव' को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने की शुरुआत भारत से हुई है। उन्होंने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, तब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ही इसके प्रथम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आज 24 अन्न भंडारण गोदाम और 64 मिलेट आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण, दुग्ध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण, दो उत्कृष्ट प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का सम्मान किया गया। साथ ही, श्वेत क्रांति 2.0 – प्राइमरी डेयरी कोआपरेटिव सोसाइटी (PDCS) ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम अभियान के तहत सफलता की कहानियों के संकलन तथा वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सफलता की कहानियों के संकलन का विमोचन किया गया। इसके अलावा, राजस्थान पुलिस एवं सशस्त्र बलों को दिए गए 100 नए

वाहनों को फ्लैग-ऑफ किया गया।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर गांव, गरीब और किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ केन्द्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आज 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है और आगामी 100 साल सहकारिता के होंगे। श्री शाह ने कहा कि देश के धान और गेहूं की खरीद में लगभग 20 प्रतिशत योगदान सहकारिता का है, जबकि 35 प्रतिशत उर्वरक और 30 प्रतिशत चीनी का उत्पादन सहकारिता के माध्यम से होता है। 20 प्रतिशत से ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें (फेयर प्राइस शॉप) भी सहकारिता के माध्यम से चलती हैं। उन्होंने कहा कि 8 लाख 50 हजार सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। ■

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल का संकल्प

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई, 2025 को अपनी सफल अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल पृथ्वी पर वापस आ गए। यह समस्त भारतवासी के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। यहां प्रस्तुत है केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प का संपादित पाठ:

मंत्रिमंडल 16 जुलाई को कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ देश की एक महान उपलब्धि से जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अन्तरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है।

आज मंत्रिमंडल देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया। ये मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में शामिल हुए। इस मिशन के जरिए पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम का एक नया अध्याय है। ये अन्तरिक्ष में भारत की एक बड़ी उड़ान है एवं हमारे स्पेस प्रोग्राम के भविष्य की स्वर्णिम झलक देता है।

मंत्रिमंडल इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो के साथ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता है। उनकी निष्ठा, तपस्या और परिश्रम ने इस सपने को साकार किया।

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने Axiom-4 क्रू और Expedition 73 के सदस्यों के साथ मिलकर अनेक प्रयोग किए। ये इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन में भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका का प्रमाण है।

उन्होंने माइक्रोग्रैविटी से जुड़े कई प्रयोग किए। Muscle regeneration, शैवाल एवं सूक्ष्मजीवों की ग्रोथ और अंतरिक्ष में फसलों की क्षमता से जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधान इसमें शामिल थे। इस मिशन में माइक्रोब्स के जीवन की संभावनाएं और इंसान की सोचने-समझने की क्षमता पर अंतरिक्ष के असर का अध्ययन भी हुआ। सायनोबैक्टीरिया जैसे जीवों के व्यवहार जैसे कई अहम विषयों पर काम किया गया।

इन प्रयोगों से अंतरिक्ष में मानव जीवन को लेकर समझ और गहरी होगी, माइक्रोग्रैविटी साइंस में हम आगे बढ़ेंगे।

भारत 'गगनयान मिशन' के जरिए और भी बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहा है

भारत आने वाले समय में गगनयान मिशन के जरिए और भी बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहा है। हमने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का संकल्प भी लिया है। शुभांशु शुक्ला के मिशन की इस सफलता ने भारत को अपने इन लक्ष्यों के एक कदम और करीब पहुंचा दिया है। भारत अब मानव अंतरिक्ष मिशन की बड़ी शक्तियों में से एक बनने की ओर अग्रसर है।

मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना करता है। उनकी दूरदृष्टि, भारत की स्पेस क्षमताओं पर उनके अटल विश्वास और उनके मार्गदर्शन ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। सरकार को इस बात पर गर्व है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। 23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। इस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह आदित्य-L1 मिशन ने सूर्य के रहस्यों को समझने में नई दिशा दी है। ये उपलब्धियां भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा और आत्मनिर्भरता का प्रमाण हैं।

सरकार ने स्पेस सेक्टर में जो सुधार किए हैं, उससे भारत की स्पेस इकॉनॉमी को अभूतपूर्व गति मिली है। इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और technology-driven development का नया इकोसिस्टम तैयार हुआ है।

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे। मंत्रिमंडल का दृढ़ विश्वास है कि ये मिशन विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसे नई मजबूती मिलेगी। ■

लंदन (ब्रिटेन) में 23 जुलाई, 2025 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर से मुलाकात करते तथा भारतीय समुदाय का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

माले (मालदीव) में 25 जुलाई, 2025 को मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

मालदीव में 26 जुलाई, 2025 को भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में 18 जुलाई, 2025 को विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

मोतिहारी (बिहार) में 18 जुलाई, 2025 को विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 04 अगस्त, 2025
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953

छायाकार: अजय कुमार सिंह